सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 55, नई दिल्ली । मंगलवार, 07 मई 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

एक मिनट की सफलता बरसों की असफलता की कीमत चुका देती है।

03 धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद केंद्र सरकार सख्त....
06 भारत 2047 तक ऐसे बनेगा विकसित देश
08 उडीशा मे बीजेपी सरकार बनाएगी , 10 जून को बीजेपी मुख्यमंत्री शपथ लेगा : मोदी

4 मई 2017 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा FADA के पत्र पर जारी किया गया था स्पष्टीकरण जिसे दिल्ली परिवहन विभाग ने आज तक नही माना, आखिर क्यों?

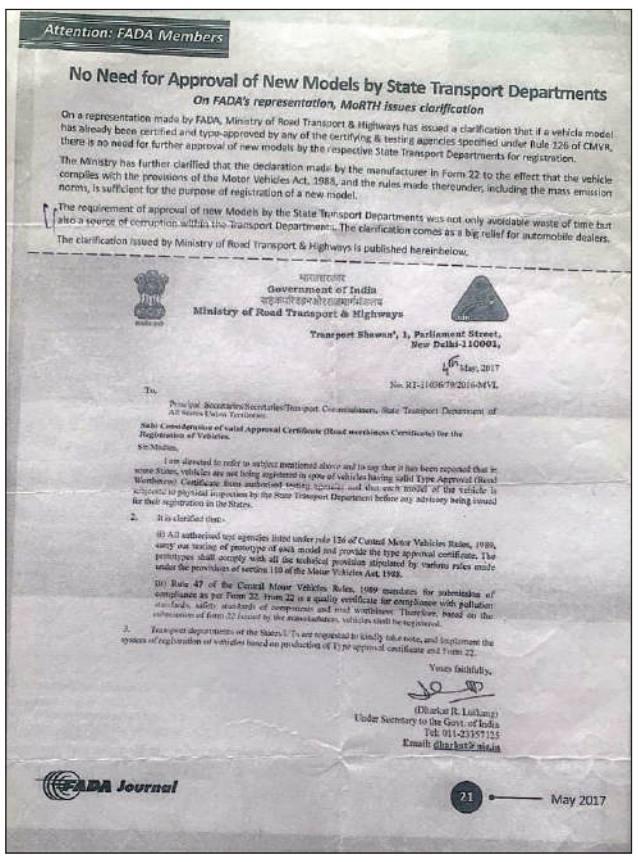

Attention: FADA Members

No Need for Approval of New Models by State Transport Departments

On FADA's representation, MoRTH issues clarification

On a representation made by FADA, Ministry of Road Transport & Highways has issued a clarification that if a vehicle model has already been certified and type-approved by any of the certifying & testing agencies specified under Rule 126 of CMVR, there is no need for further approval of new models by the respective State Transport Departments for registration.

The Ministry has further clarified that the declaration made by the manufacturer in Form 22 to the effect that the vehicle complies with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the rules made thereunder, including the mass emission norms, is sufficient for the purpose of registration of a new model.

The requirement of approval of new Models by the State Transport Departments was not only avoidable waste of time but also a source of corruption within the Transport Departments. The clarification comes as a big relief for automobile dealers.

The clarification issued by Ministry of Road Transport & Highways is published hereinbelow.

भारतसरकार
Government of India
सड़कपरिवहनऔरराजमार्गमंत्रालय
Ministry of Road Transport & Highways

Transport Bhawan', 1, Parliament Street, New Delhi-110001,

4th May, 2017

No. RT-11036/79/2016-MVL

To,

Principal Secretaries/Secretaries/Transport Commissioners, State Transport Department of All States/Union Territories.

Sub: Consideration of valid Approval Certificate (Road worthiness Certificate) for the Registration of Vehicles.

Sir/Madam,

I am directed to refer to subject mentioned above and to say that it has been reported that in some States, vehicles are not being registered in spite of vehicles having valid Type Approval (Road Worthiness) Certificate from authorised testing agencies and that each model of the vehicle is subjected to physical inspection by the State Transport Department before any advisory being issued for their registration in the States.

2. It is clarified that:-

(i) All authorised test agencies listed under rule 126 of Central Motor Vehicles Rules, 1989, carry out testing of prototype of each model and provide the type approval certificate. The prototypes shall comply with all the technical provision stipulated by various rules made under the provisions of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988.

(ii) Rule 47 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 mandates for submission of compliance as per Form 22. Form 22 is a quality certificate for compliance with pollution standards, safety standards of components and road worthiness. Therefore, based on the submission of form 22 issued by the manufacturers, vehicles shall be registered.

3. Transport departments of the States/UTs are requested to kindly take note, and implement the system of registration of vehicles based on production of Type approval certificate and Form 22.

Yours faithfully,

(Dhirkar R. Lulliang)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23357125
Email: dhirkar@nic.in

FADA Journal 21 May 2017

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग किसी (माननीय सर्वोच्च न्यायालय, गृह मंत्री सचिव कमेटी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उच्च न्यायालय, केट) के भी द्वारा जारी गैजेट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, आदेश, दिशा निर्देश, एडवाइजरी और स्पष्टीकरण को तब तक नही मानता और लागू नहीं करता जब तक वह उसके अपने हित में नहीं हो, काफी अरसे से इस बात के लिए परिवहन विभाग सुर्खियो में है। ऐसे गैजेट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन, आदेश, दिशा-निर्देश, एडवाइजरी और स्पष्टीकरण जो जनहित में हो पर दिल्ली परिवहन विभाग के हित मे ना हो को लागू करवाने के लिए वाहन मालिकों/चालकों के हित मे कार्यरत यूनियन, संस्थाएं कितना भी प्रयास कर ले पर कम ही सफल हो पाती है। **आखिर क्यो नही जारी करता इन्हे दिल्ली परिवहन विभाग ?** ऐसा ही एक स्पष्टीकरण फिर से सामने आया है जो 4 मई 2017 को जारी हुआ था और आश्चर्य की बात जो सामने आ रही है वह है इसे जारी करवाने वाली संस्था। क्योंकि इस संस्था का भारत देश के साथ दिल्ली में इतना वजूद है कि अपनी इच्छा के कार्यों के आदेश दिल्ली परिवहन के आला अधिकारियों से कभी भी करवाती रहती है। ऐसी संस्था के द्वारा जारी करवाया गया स्पष्टीकरण और वह भी ऐसे मुद्दे पर जो कानून की दृष्टि में भारत देश के सभी राज्यों के सभी परिवहन विभागों को बिना स्पष्टीकरण के ही लागू रखना चाहिए को भी दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा आज तक क्यों नहीं माना गया। आप सभी की जानकारी हेतु बता दें की भारत देश में कोई भी वाहन (निजी प्रयोग या व्यवसायिक प्रयोग में आने वाला) भारत देश में मान्यता प्राप्त चार टेस्टिंग सेंटर में से किसी एक टेस्टिंग सेंटर से सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना पंजीकृत ही नहीं हो सकता और जो सर्टिफिकेट टेस्टिंग के बाद इन चारों में से किसी भी सेंटर द्वारा जारी किया जाता हैं वह सम्पूर्ण भारत में मान्य होता है फिर राज्य परिवहन विभाग किस लिए इस सर्टिफिकेट के जारी होने के बाद राज्य से इसी सर्टिफिकेट को जो आनलाइन उपलब्ध है को वाहन निर्माता से जमा करवा कर राज्य माडल अप्रूवल लेने के लिए बाध्य करता है ? यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि **क्या राज्य परिवहन विभाग इन टेस्टिंग सेंटर द्वारा जारी प्रमाण पत्र को जो वाहन के टेस्ट होने के बाद भारत में पंजीकरण के लिए जारी किया गया है को नही मानता और अपने राज्य से माडल अप्रूवल लेने के लिए बाध्य करता है ?** दुसरा सवाल खास तौर से दिल्ली परिवहन विभाग से **अगर दिल्ली परिवहन विभाग की नज़र मे इन चारो टेस्टिंग सेंटर द्वारा वाहन टेस्ट होकर पंजीकरण के लिए जारी प्रमाण पत्र होने पर भी दिल्ली में वाहन पंजीकरण करवाने के लिए अलग से माडल अप्रूवल लेना आवश्यक है तो वह वाहन निर्माताओं को यह छुट दे दे की उन्हे दिल्ली राज्य में अपना वाहन पंजीकरण करवाने के लिए दिल्ली के माडल अप्रूवल के अलावा किसी अन्य टेस्टिंग सेंटर से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। *क्या दिल्ली परिवहन विभाग में कार्यरत आला अधिकारी आदेश पारित कर वाहन निर्माताओं का उन चार टेस्टिंग सेंटर में जा कर समय और फीस खराब करने से बचाने का कदम उठाएगा।**

यह दृश्य सेक्टर -12 कोर्ट रोड का हैं, अभी कुछ दिन पहले पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं करवाने और सड़क पर गाड़िया पार्क करवाने को लेकर बैंक्वेट हाल संचालकों पर मुकदमा दर्ज हुआ, तो इस दृश्य के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा और इसके लिए किसी पर मुकदमा दर्ज होगा।

लंबित देय यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत 11 मई 2024 (शनिवार) को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दिल्ली के सभी अदालत परिसरों में आयोजित की जाएगी। लंबित चालान/नोटिस का भुगतान करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं। @DSLSA_DELHI

सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा : नोएडा यातायात प्राधिकरण यातायात उल्लंघनों पर सख्ती बरत रहे हैं

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों को बनाए रखने के लिए एक ठोस प्रयास में, नोएडा यातायात अधिकारियों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ अपने प्रवर्तन उपायों को तेज कर दिया है।

पिछले हफ्तों में कई मौकों पर, अधिकारियों ने अनधिकृत पार्किंग क्षेत्रों में पाए जाने वाले वाहनों, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और वैध परमिट के बिना चलने वाले वाहनों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है। उल्लेखनीय उदाहरणों में शामिल हैं:

अट्टा चौक: अवैध परमिट के साथ परिचालन करने और यातायात नियमों की अनदेखी करने पर ऑटो-रिक्शा, टेम्पो और ई-रिक्शा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

डी-मार्ट गोलचक्कर, ग्रेटर नोएडा: अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए गए।

गौर सिटी-2 सर्विस रोड: सड़कों पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, अनधिकृत पार्किंग क्षेत्रों में खड़े पाए गए वाहनों से तुरंत निपटा गया।

इको विलेज-2 रूट: सड़क सुरक्षा मानदंडों के पालन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों, विशेष रूप से विपरीत दिशा में चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

ये प्रयास सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और शहर के भीतर यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नोएडा यातायात प्राधिकरण के समर्पण को रेखांकित करते हैं। लगातार प्रवर्तन कार्रवाइयों और जन जागरूकता पहलों के माध्यम से, उनका लक्ष्य मोटर चालकों और पैदल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है।

इसके अलावा, अधिकारियों ने ट्रैफिक चालान के स्नैपशॉट साझा करने के लिए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों का लाभ उठाया है, जिससे ट्रैफिक नियमों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है।

जैसे-जैसे शहर का विकास जारी है, नोएडा यातायात अधिकारियों के ऐसे सक्रिय उपाय सभी निवासियों के लिए सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने और समुदाय की सामूहिक भलाई के लिए यातायात कानूनों का पालन करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं।

किसी भी यातायात संबंधी चिंता या आपात स्थिति के लिए, निवासियों से 0-9971009001 पर समर्पित हेल्पलाइन पर पहुंचने का आग्रह किया जाता है।

डॉ अंकुर शरण
राष्ट्रीय मुख्य यातायात एवं नियोजन अधिकारी
सड़क सुरक्षा ओमनी फाउंडेशन
roadsafetysquad@gmail.com

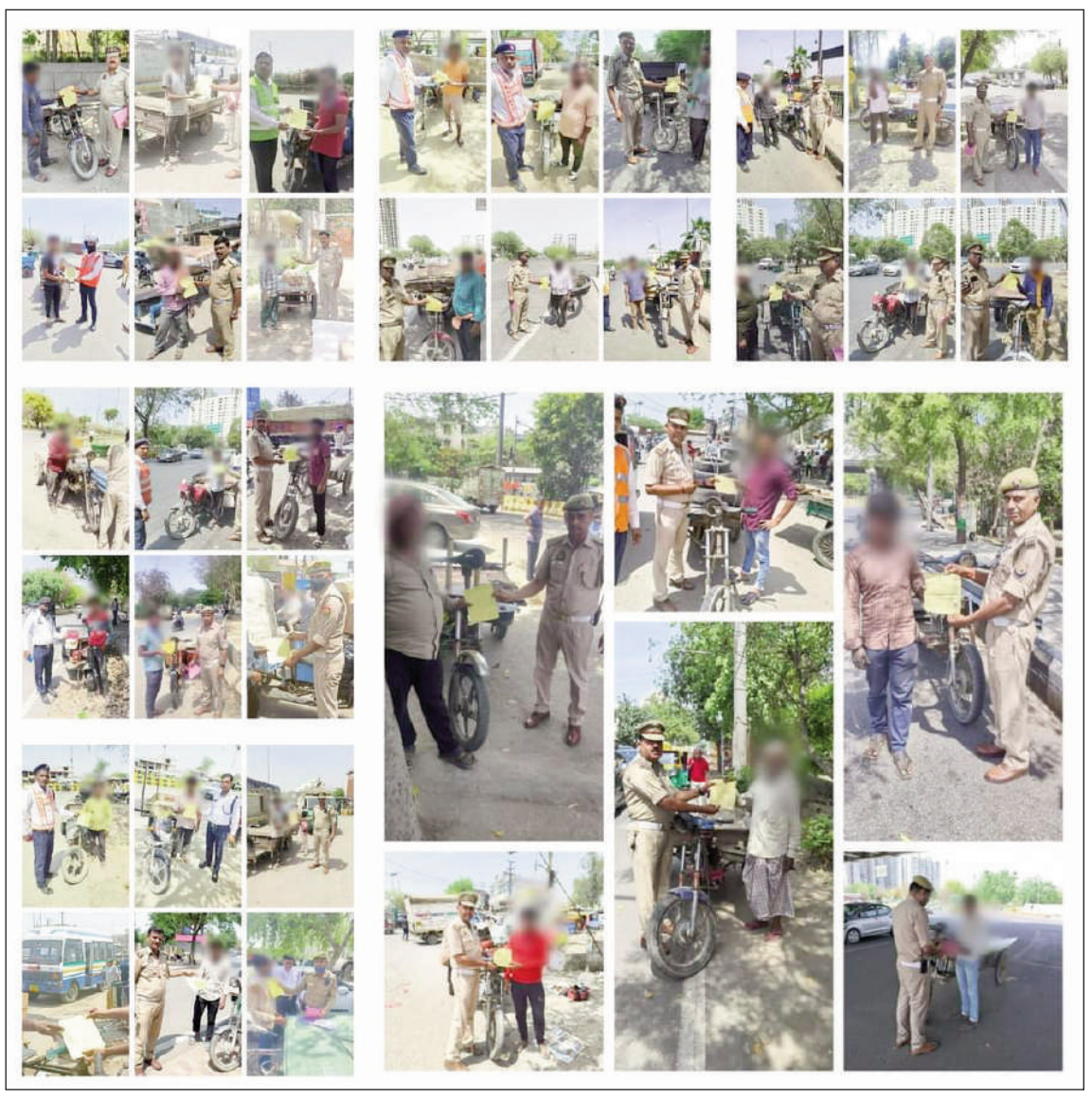

वीआईपी मूवमेंट के दौरान कार ने सीआरपीएफ जवान को मारी टक्कर, अस्पताल में चल रहा इलाज; हालत गंभीर

दिल्ली कैंट इलाके में वीआईपी मूवमेंट के दौरान तेज रफ्तार कार ने सीआरपीएफ के एक जवान को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल जवान को आरआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

दिल्ली कैंट इलाके में वीआईपी मूवमेंट के दौरान तेज रफ्तार कार ने सीआरपीएफ के एक जवान को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। अन्य साथियों ने घायल जवान को आरआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घायल जवान की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक कार को मौके पर छोड़ कर फरार हो गया। पुलिस ने कार नंबर के जरिए आरोपी देवदत्त को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है।

घायल अनिल कुमार सीआरपीएफ में बतौर हवलदार कार्यरत हैं। उनकी तैनाती जाफराबाद इलाके में है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 4 मई की रात करीब पौने दस बजे पुलिस को धौलाकुआं इलाके में सड़क हादसा होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर एक कार मिली। कार के शीशे टूटे हुए थे। मौके पर सीआरपीएफ का एक जवान अशोक कुमार मिला।

उन्होंने बताया कि उनकी धौलाकुआं में वीआईपी मूवमेंट में तैनाती थी। रात में मूवमेंट खत्म होने के बाद वह अपने साथी हवलदार अनिल कुमार के साथ स्टाफ बस की ओर जा रहे थे। सड़क पार करने के दौरान एक कार उनकी तरफ तेज रफ्तार से आई। उन्होंने कार चालक को रुकने का इशारा किया। लेकिन तब तक कार ने अनिल को जोरदार टक्कर मार दी।

पर्यावरण पाठशाला : गार्बेज क्लिनिक के नायक और उनकी प्रगति की प्रेरक कहानी -अंकुर

गार्बेज क्लिनिक एक सामुदायिक संगठन है जो साफ सफाई, पर्यावरण संरक्षण, और स्वच्छता के क्षेत्र में काम करता है। हमने नई परिभाषा दी है और कूड़ाघर को ₹गार्बेज क्लिनिक₹ और कूड़ा गाड़ी को ₹गार्बेज एंबुलेंस₹ कहा है। हमारा मकसद लोगों को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक सोच देना है।

गार्बेज क्लिनिक के नायक और उनकी प्रगति

जन्म स्थान - नौगांव (बुंदेलखंड) मध्यप्रदेश

धर्म पत्नी - प्रगति

शिक्षा - डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स , BE Electrics & Telecommunication

Job - मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ।

भारत की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट

जीवन प्रभावित - माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान प्रमुख रूप से देश के लिए कुछ करने का विचार ।

संयोग - अंबिकापुर (ससुराल) में IAS अधिकारी और तत्कालीन कलेक्टर श्रीमती ऋतु सेन जी से परिचय और उनके स्वच्छ भारत अभियान, शहरी आजीविका मिशन के अनुकरणीय समायोजन का अवलोकन करने का सौभाग्य ।

दिल्ली की विभीषिका का दृष्टा गाजीपुर कूड़े का पहाड़ का गिरना और उसमे दबकर लगभग 4 लोगो की दर्दनाक मौत को देख कर मन का व्यथित होना , कंपनी से उसी दिन त्यागपत्र देना और गार्बेज क्लिनिक का गठन करना ।

समाज द्वारा मजाक बनाना और संघर्ष के दिन तत्कालीन कंपनी के मैनेजमेंट और मित्रो द्वारा मजाक उड़ाया गया , कुछ ने पागल तो कुछ ने डिप्रेशन का मरीज तक बोल दिया , कंपनी को फ्रेशर के रूप में कोई काम नहीं दिया , सरकारी सिस्टम में जगह नहीं ।

भारत के विभिन्न स्वच्छता मॉडल्स का इस दौरान किया अध्ययन और तैयार हुआ एक मॉडल गार्बेज क्लिनिक ।

बिना दुर्गन्ध का एक ऐसा कचरा घर जहा लोग अपने परिवार के साथ चाय नाश्ता तक कर सकें ।

आज जहा सोसायटी , वार्ड में लोग कूड़ाघर बनने नही देते , गार्बेज क्लिनिक ने उनकी सोच बदल दी ।

भारत में जैविक खाद की आवश्यकता और इसका उत्पादन

हर परिवार अपने बच्चो को ऑर्गेनिक फूड खिलाना चाहता है पर उपलब्ध नहीं इस डिमांड और सप्लाई को समझा ।

जैविक खाद उत्पादन केंद्र में रेगपिकर्स , गरीब महिलाओ को हिस्सेदार बनाया , ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया और इस प्रोजेक्ट में उन्हें भी शेयर होल्डर बनाया ।

गीले कूड़े को कच्चे माल के रूप में किया उपयोग ।

नगर पालिका और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिग कंपनी (APMC) का किया समायोजन और इस तरह जन्म हुआ फार्मर्स क्लिनिक का

स्वच्छता मिशन ऑर्गेनिक आत्मनिर्भर मॉडल हो गया तैयार ।

स्वास्थ्य भारत अभियान को बल

जो परिवार गीला , सूखा , घातक कूड़ा सीग्रीगेट कर के देते है , फार्मर्स क्लिनिक के सदस्य उन्हें उचित मूल्य पर ऑर्गेनिक सब्जी , ऑर्गेनिक फल की डोर टू डोर सप्लाई करते हैं ताकि लोग स्वास्थ्य रह सके ।

भारत में शुरू की नई परिभाषा

कूड़ाघर - गार्बेज क्लिनिक

कूड़ा गाड़ी - गार्बेज एंबुलेंस

यूनिवर्सिटीज के लिए इंस्टीट्यूशनल स्वच्छता मॉडल्स

जागरूकता का सुपर हिट गीत का प्रोडक्शन - **गाड़ीवाला आया घर से कचरा निकाल** , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पहला जीरो वेस्ट सेक्टर नोएडा सेक्टर 47 को 2018 में बनाया ।

भारत का पहला इंस्टीट्यूशनल वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के लिए तैयार किया ।

बीड महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कैंपस में नगर पालिका और मार्केटिंग कंपनी के सहयोग से 10,000 किलो गीले कूड़े से जैविक खाद बनाने की फैक्ट्री तैयार की जिसमे लगभग 5000 किसानों को शेयर होल्डर बनाया।

आज , गार्बेज क्लिनिक देश के विभिन्न राज्यों में अभी तक सैकड़ों मीट्रिक टन कूड़े का कर दिया निस्तारण , 5000 टन प्लास्टिक को करवाया रीसाइकल , एक दर्जन से ज्यादा राज्य ले रहे है सेवाए , 3000 से भी ज्यादा कर चुके है छोटी बड़ी वर्कशॉप , 5000 से ज्यादा बैलेंटियर है ऑन बोर्ड, 100 से ज्यादा कॉलेज , 25 से ज्यादा यूनिवर्सिटी , 10 एनवायरमेंटल रिचर्च सेंटर्स हो चुके है ऑन बोर्ड , 5,000 से ज्यादा रैगपिकर्स ले चुके है अभी तक ट्रेनिंग ।

सपोर्ट- बचपन के मित्र अनुराग गुरु उनकी पत्नी सुजाता गुरु ने इस संस्था में संघर्ष के दिनों में सहयोग किया ।

कुमार गौतम उनकी पत्नी आशिमा ने कंपनी को खड़ा करने में सहयोग किया ।

दिल्ली के चार्टेड एकाउंटेंट श्री विनीत कुमार ने रजिस्ट्रेशन की फीस तक अपनी जेब से दे दी थी ।

पुरुस्कार विभिन्न राज्यों , यूनिवर्सिटीज , मिनिस्ट्रीज , सामाजिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान सेंटर्स , नगरीय प्रशासन , कॉर्पोरेट्स , धार्मिक संस्थाओं , मीडिया , सोशल चैनल्स यूट्यूब , द्वारा गार्बेज क्लिनिक को उनके पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक बदलाव , के लिए लगातार पुरुस्कृत किया जा रहा है ।

अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय भूमिका ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए UN द्वारा भारत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने की दिशा में गार्बेज क्लिनिक देश के बड़े कॉर्पोरेट्स के सीएसआर प्रोग्राम के साथ कार्य कर रही हैं।

indiangreenbuddy@gmail.com

चुनावों में संवादों का गिरता स्तर जिम्मेदार कौन ?

भारत की वसुंधरा पर अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने अपने स्वार्थ का त्याग कर देशहित के लिये ही जीवन पर्यंत कार्य किये।

लेकिन आज वर्तमान भारत में राजनीति के चुनाव की स्थिति देखकर मन में संशय होता है कि जो नेता प्रमुख अपनी पार्टी को आगे लाने में, विपक्ष पार्टी पर निम्न स्तरीय संवादों का उपयोग कर रहे हैं क्या वह उचित है ?

एक अच्छे नेता के स्वाभाविक गुण - मैत्री,पवित्रता,प्रबोधता, देशप्रेम की भावना व अपने साथियों के प्रति आदर की भावना आदि आज के नेताओं में दिखाई नहीं देते जो कि चिंतनीय है।

जब नेता प्रमुख ही गलत जा रहा हो तो उसके संगठन की दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है...और ऐसे नेतृत्व में अगर देश की बागडोर थमा दी जाए तो समाज ही नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र का पतन सुनिश्चित है।

इस भयावह स्थिति के जिम्मेदार वो आम नागरिक भी हैं जो पैसे की खातिर किसी पार्टी विशेष से मिल जाते हैं और उचित अनुचित का बोध खोकर उनकी सिखाई नफरत भरी भाषा ही प्रयोग कर रहे हैं।

आज ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमें अपनी सोच और वाणी शुद्ध रखनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि देशहित में उसी नेता को चुना जाए जिसकी वाणी पर संयम हो और जो कटु वचनों का प्रयोग कर देश को अखंडता व अक्षुणता को हानि ना पहुंचाए।

सविता गुप्ता
-प्रयागराज

संस्कारशाला : प्रभावी सार्वजनिक भाषण संबोधित करने के लिए यहां कुछ विशेष युक्तियां और तकनीकें : प्रियंका श्रीवास्तव

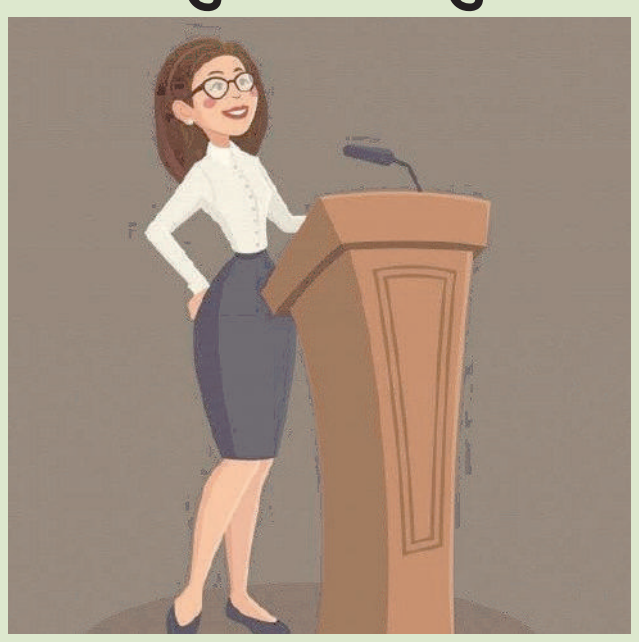

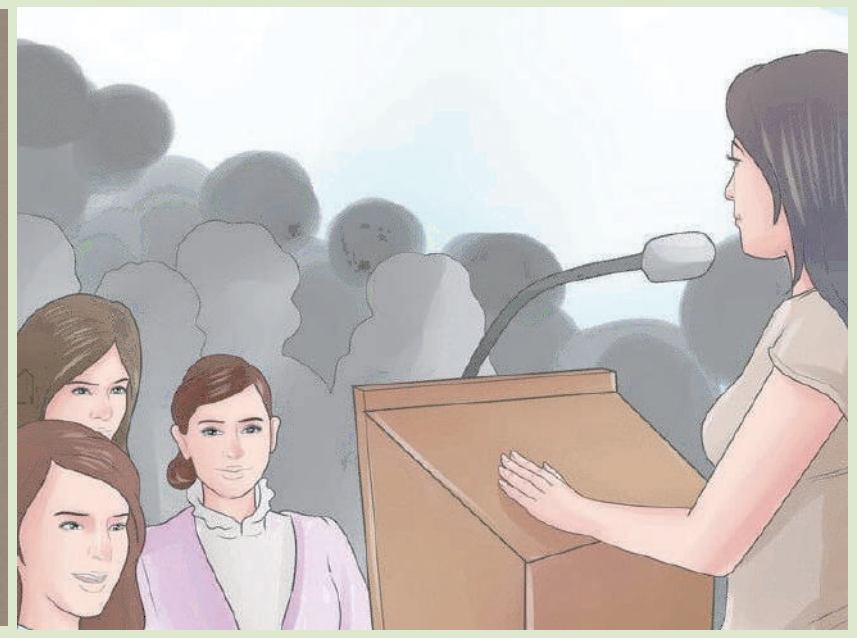

अपनी सामग्री में महारत हासिल करें:

अपनी सामग्री को अंदर से जानें। आत्मविश्वास योग्यता से आता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने विषय के बारे में अच्छी तरह से तैयार और जानकार हैं।

मजबूत शुरुआत करें:

एक सम्मोहक शुरुआत के साथ शुरुआत से ही ध्यान आकर्षित करें। यह एक चौंकाने वाला आँकड़ा, एक विचारोत्तेजक प्रश्न या आपके विषय से संबंधित एक मनोरम कहानी हो सकती है।

स्पष्ट और धीरे बोलें:

अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से कहें और खुद को गति दें। यह दर्शकों को आपके संदेश को प्रभावी ढंग से पचाने की अनुमति देता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई इसका अनुसरण कर सके।

शारीरिक भाषा का प्रयोग करें:

आपकी शारीरिक भाषा आपके शब्दों से ज्यादा नहीं तो उतनी ही बात बता सकती है। आंखों का संपर्क बनाए रखें, बिंदुओं पर जोर

देने के लिए इशारों का उपयोग करें और अपनी मुद्रा के माध्यम से आत्मविश्वास प्रदर्शित करें।

दर्शकों को शामिल करें:

प्रश्न पूछकर, भागीदारी को आमंत्रित करके, या अपनी प्रस्तुति में गतिविधियों को शामिल करके बातचीत को प्रोत्साहित करें। इससे श्रोता जुड़े रहते हैं और आपकी बातचीत अधिक यादगार बन जाती है।

अपना संदेश तैयार करें:

अपने दर्शकों को समझें और अपने संदेश को उनके अनुरूप ढालें। उनकी भाषा बोलें, उनकी चिंताओं का समाधान करें और प्रासंगिक उदाहरण प्रदान करें जिनसे वे संबंधित हो सकें।

कहानियाँ सुनाएँ:

कहानियों में भावनात्मक स्तर पर लोगों को लुभाने और उनसे जुड़ने की एक अनोखी शक्ति होती है। अपनी बातों को स्पष्ट करने और उन्हें अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उपाख्यानों, केस अध्ययनों या व्यक्तिगत अनुभवों को शामिल करें।

विजुअल एड्स का बुद्धिमानी से उपयोग करें:

स्लाइड या प्रॉप्स जैसे विजुअल एड्स आपकी प्रस्तुति को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने संदेश पर हावी न होने दें। अपने भाषण से ध्यान भटकाने के बजाय समर्थन के लिए उन्हें सरल, प्रासंगिक और देखने में आकर्षक रखें।

अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास:

किसी भी गड़बड़ी को दूर करने और सुचारू प्रस्तुति सुनिश्चित करने के लिए अपने भाषण का कई बार अभ्यास करें। अपने समय, गति और लहजे पर ध्यान दें और विश्वसनीय साथियों या आकाओं से प्रतिक्रिया मांगें।

प्रभाव के साथ समाप्त करें:

एक यादगार समापन वक्तव्य के साथ जोरदार समापन करें जो आपके मुख्य संदेश को पुष्ट करता है और आपके दर्शकों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है।

याद रखें, प्रभावी सार्वजनिक भाषण एक ऐसा कौशल है जिसे अभ्यास और दृढ़ता से निखारा जा सकता है। इसलिए, अपनी तकनीक को निखारते रहें और खुद को वहां पेश करने से न डरें !

पितृ कार्य अमावस्या 07 मई 2024 , मंगलवार

आज 07 मई 2024 मंगलवार को पितृ कार्य अमावस्या और अमृत सिद्धि व सर्वार्थ सिद्धि जैसे श्रेष्ठ शुभ योग विद्यमान रहेंगे। अतः जब भी इस तरह के कुछ विशेष योग पड़े तो उस दिन कुछ विशेष जरूर करना चाहिए।

* ज्योतिष के अनुसार ऐसे विशेष योग पर ग्रह शांति व कुंडली में विद्यमान अशुभ दोष के निवारण के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय जरूर करने चाहिए।

* अमावस्या के दिन जब इस तरह के श्रेष्ठ योग पड़े और आपकी कुंडली में पितृ दोष/ कालसर्प दोष/ या फिर राहु से संबंधित व सूर्य ग्रहण/ चंद्र ग्रहण जैसे यदि कोई अशुभ दोष है तो उसके उपाय करके अशुभ दोष का प्रभाव कम किया जा सकता है। अतः किसी ज्योतिष से कुंडली परामर्श लेकर कुंडली में विद्यमान अशुभ दोष के उपाय जरूर करने चाहिए।

* मंगलवार का दिन, सर्वार्थ सिद्धि व अमृत सिद्धि जैसे श्रेष्ठ शुभ योग है अतः संभव हो सके जहां तक श्रीहनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर अर्पित करें और श्रीहनुमान चालीसा व सुंदरकांड के पाठ तो कम से कम जरुर करें।

*ऐसे विशेष योग के दिन दान- पुण्य का भी विशेष महत्व रहता है अतः किसी सात्विक साधक व्यक्तित्व के व्यक्ति को दक्षिणा इत्यादि भेंट करें और गौशाला में गायों के लिए चारा- पानी की व्यवस्था करें।

* इस दिन आप पशु- पक्षियों के लिए दाना- पानी की व्यवस्था करें। पक्षियों के लिए पानी के परिंडे लगाए।आप अमावस्या से शुरू करके पूरी गर्मी प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालें व पानी के परिंडों मे पानी की व्यवस्था करें।।

* अपने आस- पास पार्क व सार्वजनिक जगहों पर लगे हुए छोटे पेड़- पौधों में पानी की व्यवस्था करें और पेड़ पौधों को गर्मी में सूखने से बचाए।।

इस तरह से हम अपने जीवन के खाते में पुण्यों का बैलेंस इकट्ठा करें। और विशेष कर इन विशेष दिनों में जब हम कोई छोटा सा भी पुण्य का कार्य करते हैं तो वह कई गुना शुभ फल प्रदान करता है।।

'भारत का भूगोल'

क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है— सातवाँ

जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है— दूसरा

भारत के उत्तर में कौन-कौन-से देश हैं— चीन, नेपाल, भूटान

भारत के पूर्व में कौन-सा देश है— बांग्लादेश

भारत के पश्चिम में कौन-सा देश है— पाकिस्तान

भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन-सा सागर है— अरब सागर

भारत के दक्षिण-पूर्व में कौन-सी खाड़ी है— बंगाल की खाड़ी

भारत के दक्षिण में कौन-सा महासागर है— हिन्द महासाग

पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं— म्यांमार से

मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं— श्रीलंका से

संपूर्ण भारत की अंक्षाशीय विस्तार कितना है— 8 4' से 376' उत्तरी अक्षांश

भारत के मध्य से कौन-सी रेखा गुजरती है— कर्क रेखा

भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है— 3214 किमी

भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है— 2933 किमी

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है— बंगाल की खाड़ी में

लक्षद्वीप कहाँ स्थित है— अरब सागर में

भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है— इंदिरा प्वाइंट

इंदिरा प्वांइट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है— पिगमिलियन प्वाइंट

भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है— 2.42%

विश्व की कुल जनसंख्या का कितने % भारत में निवास करता है— 17%

केजरीवाल के खिलाफ एलजी की एनआईए जांच की सिफारिश पर गरमाई सियासत, सीएम आतंकी संगठन से फंडिंग लेने का आरोप

दिल्ली के आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में जहां मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है वहीं इससे एक दिन पहले उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख उनके खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दिल्ली के आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी (आप) संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले में जहां मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है, वहीं इससे एक दिन पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिख उनके खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की है। जांच की यह सिफारिश प्रतिबंधित आतंकी संगठन 'सिख फार जस्टिस' से आप को कथित तौर पर राजनीतिक चंदा दिए जाने को लेकर एलजी को मिली एक शिकायत के आधार पर की गई है।

एलजी को मिली थी शिकायत

एलजी को शिकायत मिली थी कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को 1993 में हुए दिल्ली बम धमाके के दोषी आतंकी देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर की रिहाई में सहायता करने और खालिस्तान समर्थक भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए चरमपंथी खालिस्तानी समूहों से कथित तौर पर 16 मिलियन अमेरिकी डालर यानी 134 करोड़ रुपये मिले थे।

एलजी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में कहा है कि चूंकि आरोप सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं और देश में प्रतिबंधित आतंकी संगठन से किसी राजनीतिक दल को लाखों डालर की कथित फंडिंग से संबंधित हैं। ऐसे में शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत इलेक्ट्रानिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराए जाने की जरूरत है।

एलजी के पत्र के अनुसार, उन्हें यह शिकायत विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव आशु मोंगिया की ओर से मिली थी। अपनी शिकायत में शिकायतकर्ता ने एक वीडियो सामग्री का हवाला दिया है, जो पत्र के साथ वीडियो सुबूत के तौर पर पेन ड्राइव में गृह मंत्रालय को भेजी गई है। इसमें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप को वर्ष 2014 से 2022 के दौरान खालिस्तानी समूहों से 16 मिलियन अमेरिकी डालर की फंडिंग मिली।

केजरीवाल के एक पत्र का भी दिया हवाला

एलजी ने गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में केजरीवाल द्वारा जनवरी 2014 में लिखे गए एक पत्र का भी हवाला दिया है, जो उन्होंने भुल्लर की रिहाई के लिए लिखित आश्वासन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे इकबाल सिंह को लिखा था। इसमें केजरीवाल ने इकबाल सिंह को लिखा है कि आप सरकार पहले ही राष्ट्रपति को भुल्लर की रिहाई की सिफारिश कर चुकी है और अन्य मुद्दों पर काम करेगी, जिसमें सहानुभूतिपूर्वक और समयबद्ध तरीके से एसआइटी का गठन भी शामिल है। केजरीवाल का पत्र मिलने के बाद इकबाल सिंह ने अपना अनशन खत्म कर दिया था।

खालिस्तान समर्थक नेताओं के साथ फोटो का भी जिक्र

केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में एलजी ने यह भी कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट की एक श्रृंखला में आप के एक पूर्व कार्यकर्ता मुनीश कुमार रायजादा ने खालिस्तान समर्थक नेताओं के साथ केजरीवाल की मुलाकात की कथित तस्वीरें भी साझा की थीं।

कौन है देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर

वर्ष 1993 में दिल्ली में रायसीना रोड पर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यालय के बाहर एक कार में धमाका हुआ था। इस धमाके में रिमोट कंट्रोल आरडीएक्स बम का इस्तेमाल किया गया था। यह हमला खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ खुलकर बोलने वाले मनिंदर सिंह बिट्टा को निशाना बनाते हुए किया गया था, हमले के समय वह अपनी कार से कार्यालय से बाहर निकल रहे थे। धमाके में वह घायल हुए थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी, जबकि उनके दो सुरक्षा गार्डों समेत नौ लोगों की मौत हुई थी और 31 अन्य घायल हुए थे। इस धमाके के लिए भुल्लर को पहले मृत्युदंड दिया गया था, लेकिन बाद में उसकी सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया और वह जेल में बंद है। आतंकी भुल्लर इस हमले से पूर्व लुधियाना में केमिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर था।

दिल्ली की सियासत गरमाई

एलजी के इस कदम से दिल्ली की सियासत गरमा गई है। आप नेताओं ने एलजी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। एलजी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा दिल्ली की सभी सीटें हार रही है, इसीलिए बौखलाहट में यह कदम उठाया गया है। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत करने वाला आशू मोंगिया भाजपा का पदाधिकारी है। लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा पदाधिकारी द्वारा इस तरह का आरोप लगाने का उद्देश्य साफ दिखाता है कि इसके पीछे बड़ी साजिश है।

उल्लेखनीय है कि तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को विगत 21 मार्च को ईडी ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद कुछ दिन ईडी रिमांड में रखे जाने के बाद अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था, तभी से वह जेल में हैं। केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव में प्रचार का हवाला देते हुए जमानत की मांग की है, उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है।

> “ एलजी के इस कदम से दिल्ली की सियासत गरमा गई है। आप नेताओं ने एलजी पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह केजरीवाल के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। एलजी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा दिल्ली की सभी सीटें हार रही है, इसीलिए बौखलाहट में यह कदम उठाया गया है। आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत करने वाला आशू मोंगिया भाजपा का पदाधिकारी है....

दिल्ली सरकार और पुलिस बच्चों की निकासी से लेकर बम की धमकी मिलने पर होने वाली कार्रवाई पर पेश करें रिपोर्ट: हाईकोर्ट

परिवहन विशेष न्यूज

स्कूलों में बम की धमकी मिलने पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों और बिना घबराए बच्चों की निकासी सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में आयोजित मॉक ड्रिल की संख्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। अदालत ने अधिकारियों से 10 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा।

नई दिल्ली। स्कूलों में बम की धमकी मिलने पर कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारियों और बिना घबराए बच्चों की निकासी सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में आयोजित मॉक ड्रिल की संख्या पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अधिकारियों से प्रत्येक क्षेत्र में स्कूलों की संख्या और बम की धमकी के मामले में कार्रवाई के लिए नोडल अधिकारियों द्वारा उठाए जाने वाले कदम पर रिपोर्ट पेश करने को कहा।

अदालत ने अधिकारियों से 10 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा। अदालत ने पुलिस को स्कूलों में आने वाली फर्जी कॉल की जांच के लिए की गई कार्रवाई पर भी रिपोर्ट पेश करने को कहा।

फर्जी कॉल से निपटने के लिए उचित उपाय व योजना की मांग को लेकर याचिकाकर्ता अर्पित भार्गव ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है। उन्होंने हाल ही में दिल्ली के विभिन्न स्कूलों को बम की धमकी के बारे में फर्जी मेल का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली में हर कोई प्रभावित है क्योंकि हर घर में एक बच्चा है।

उन्होंने यह भी कहा कि माता-पिता सदमे में हैं और असुरक्षित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह याचिका वर्ष 2023 में दायर की थी और एक साल बीत जाने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हम किसी स्कूल में बम होने या फटने का इंतजार कर रहे हैं?

इसके जवाब में दिल्ली सरकार के स्थायी अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि इस संबंध में कई अहम उठाए गए हैं और दिल्ली पुलिस ने एक हलफनामा दायर किया है। फर्जी और वास्तविक बम धमकी काल से निपटने के लिए एक विशेष संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की गई है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 5,500 स्कूल हैं और हर स्कूल में पुलिस कर्मियों को तैनात करना मुश्किल है। इतना ही नहीं हर स्कूल में आधुनिक उपकरणों की तैनाती संभव और व्यवहार्य नहीं है। उस स्थिति से बचने और तैयारियों के लिए पुलिस ने अपनी एसओपी जारी की है। हर निजी स्कूल को सूचित किया जाता है कि क्या करना है। उन्होंने यह भी बताया कि एसओपी के अनुसार एक बार बम की धमकी मिलने पर स्कूल को पहला कदम पुलिस को सूचित करना है और दूसरा कदम बच्चों को निकालना है।

दिल्ली के स्कूलों के लिए नहीं है विशेष एसओपी

इस पर अदालत ने टिप्पणी की कि दिल्ली पुलिस की एसओपी सामान्य प्रकृति की है और राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों के लिए कोई विशेष एसओपी नहीं है। अदालत ने पीठ से पूछा कि कुछ संस्थान ऐसे हैं जिन्हें विशेष उपचार की आवश्यकता होती है।

धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद केंद्र सरकार सख्त, स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने और सीसीटीवी लगाने पर दिया जोर

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजने जाने के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की और स्कूलों में सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे और ई-मेल की नियमित निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। भल्ला ने दिल्ली पुलिस और स्कूलों से एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र के लिए नजदीकी समन्वय रखने को भी कहा ताकि झूठी सूचना से अनावश्यक दहशत न फैले।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजने जाने के मद्देनजर सोमवार को स्थिति की समीक्षा की और स्कूलों में सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और ई-मेल की नियमित निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। भल्ला ने दिल्ली पुलिस और स्कूलों से एक प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र के लिए नजदीकी समन्वय रखने को भी कहा, ताकि झूठी सूचना से अनावश्यक दहशत न फैले।

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, गृह सचिव ने पिछले सप्ताह दिल्ली के कुछ स्कूलों को मिले ईमेल के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल और एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार करने की जरूरत पर बल दिया।

सीसीटीवी कैमरे और ईमेल की निगरानी बढ़ाने पर जोर

प्रवक्ता ने कहा कि गृह सचिव ने स्कूलों में सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे और ईमेल की नियमित निगरानी बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली के पुलिस आयुक्त शामिल हुए।

200 से अधिक स्कूलों को मिले थे धमकी भरे ईमेल

दिल्ली-एनसीआर के 200 से अधिक स्कूलों को एक मई एक जैसे धमकी भरे ईमेल मिले जिनमें दावा किया गया था कि उनके परिसर में विस्फोटक लगाए गए थे। इसके बाद बड़े पैमाने पर निकासी और तलाशी अभियान चलाया गया और घबराए हुए माता-पिता अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचने लगे थे।

हालांकि तलाशी के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद में भी करीब डेढ़ दर्जन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला ई-मेल मिला, लेकिन पुलिस ने सभी विद्यालयों की तलाशी के बाद इसे फर्जी करार दिया।

दिल्ली के स्कूलों और छात्रों के लिए जरूरी खबर, केजरीवाल सरकार ने जारी किए आवश्यक निर्देश

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। स्कूलों के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने, आपदाओं को रोकने और उनसे बचाव को लेकर रणनीतियों को तैयार करने को लेकर शिक्षा निदेशालय ने मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की है। निदेशालय ने एसओपी को सभी हितधारकों के साथ साझा किया है। इसमें प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, अभिभावक और स्थानीय अधिकारी शामिल है।

निदेशालय ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि वो उन जगहों की पहचान करें, जहां से गंभीर परिस्थिति, मौसमी स्थिति या बाहरी खतरे से तुरंत स्कूल से सुरक्षित बाहर निकला जा सके। वहीं, स्कूल के अंदर भी एक सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करें और उसके लिए अलग से नियम भी स्थापित करें। इसके साथ ही बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर में स्टाफ के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें। स्कूल में सभी आवश्यक समान लैस प्राथमिक चिकित्सा कक्ष तैयार रखें।

आपातकालीन आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें

साथ ही स्कूल में आपातकालीन आपूर्ति जैसे टार्च, बैटरी, भोजन, पानी और कंबल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करें। वहीं, आपातकालीन उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण भी किया जाए। वहीं, आपातकालीन स्थिति के दौरान छात्रों, कर्मचारियों और स्कूल कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई को देखते हुए सोच-समझकर और समय पर निर्णय लें।

निदेशालय ने निर्देश दिया कि प्रधानाचार्य व्यापक विकास के लिए आपदा प्रबंधन समिति के साथ काम करें और ये सुनिश्चित करे कि स्थापित आपदा प्रबंधन नीतियों को प्रभावी ढंग से पालन किया जाए।

प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, विद्यार्थियों व स्थानीय अधिकारी के लिए निर्देश

- स्कूल परिसर के अंदर संभावित खतरों और जोखिमों की पहचान करने के लिए समिति के साथ सहयोग करें।
- आपातकालीन परिस्थिति में स्कूल से निकलने के लिए योजना तैयार रखें।
- विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति की स्थापना करना और उसका नेतृत्व करना। इसमें स्टाफ कर्मचारी, शिक्षक और अन्य संबंधित हितधारक शामिल होंगे।
- ये सुनिश्चित करें कि समिति के सदस्यों को आपदा से निपटने के लिए उचित प्रशिक्षण मिले।
- आवश्यक संसाधनों की पहचान, आपूर्ति व संचार उपकरण के लिए समिति के साथ काम करें।
- आपदाओं से निपटने के लिए बजट बनाएं।
- आपातकाल के दौरान व बाद में सुनिश्चित करें कि सूचना पहले प्रभावी ढंग से संप्रेषित की गई है।
- नियमित आपातकाल की योजना बनाने और उसका संचालन करने के लिए समिति के साथ सहयोग करें।

- यह सुनिश्चित करें कि सभी हितधारक स्कूल से सुरक्षित निकलने के प्रोटोकॉल से अच्छे से परिचित हों
- प्रशिक्षण अभ्यासों की प्रभावशीलता का आकलन करें और तैयारियों में सुधार करें।
- स्थानीय अधिकारी से साथ समन्वय स्थापित करें।
- बाहरी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करें।
- माता-पिता को स्कूल में आपदा के बारे में सूचित रखें।
- आपातकालीन स्थिति के दौरान माता-पिता को उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित करें और उन्हें स्कूल आपदा प्रबंधन योजना में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करें।
-स्कूल परिसर में और आसपास संभावित खतरों जैसे प्राकृतिक आपदाओं (भूकंप, बाढ़, तूफान), तकनीकी खतरों (बिजली कटौती, गैस रिसाव) और मानव निर्मित खतरे (घुसपैठिए, हिंसा) से निपटने के लिए तैयार रहें।
- एक आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम स्थापित करें जिसमें जिम्मेदार प्रशिक्षित व्यक्ति शामिल हों।
- प्राथमिक सदस्यों सहित टीम के सदस्यों को विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपें।
- एक स्पष्ट संचार योजना विकसित करें जिसमें यह बताया जाए कि आपात स्थिति में सूचना का प्रसार कैसे किया जाएगा।
- छात्रों, कर्मचारियों और अभिभावकों के लिए आपातकालीन संपर्क जानकारी की एक अद्यतन सूची बनाए रखें।
- सुनिश्चित करें कि संपर्क जानकारी में संचार के कई माध्यम (फोन नंबर व ईमेल) हो।
- विभिन्न प्रकार की आपात स्थितियों के लिए प्राथमिक और द्वितीयक निकासी मार्ग निर्दिष्ट करें व छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को इससे परिचित कराने के लिए नियमित निकासी अभ्यास आयोजित करें।
- आपातकाल के बाद की छात्रों, कर्मचारियों और स्कूल समुदाय को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श देना।
- आपदा प्रबंधन की प्रभावशीलता की नियमित समीक्षा और मूल्यांकन करें।
- शिक्षक विद्यार्थियों को माक ड्रिल, भूकंप सहित नियमित आपातकालीन ड्रिल का अभ्यास कराएं।
-विद्यार्थी आपातकालीन अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लें और निर्देशों का पालन करें।
- विद्यार्थी आपातकालीन निकास, निकासी मार्गों और स्थान के बारे में जागरूक हों।
- विद्यार्थी शिक्षकों या स्कूल को किसी भी संभावित खतरे या घटना की सूचना दें।
-स्थानीय अधिकारी आपदा प्रबंधन के विकास और समीक्षा के लिए स्कूलों के साथ मिलकर काम करे।

> *दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया कि वो उन जगहों की पहचान करें जहां से गंभीर परिस्थिति मौसमी स्थिति या बाहरी खतरे से तुरंत स्कूल से सुरक्षित बाहर निकला जा सके। वहीं स्कूल के अंदर भी एक सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करें और उसके लिए अलग से नियम भी स्थापित करें। स्कूल में सभी आवश्यक समान लैस प्राथमिक चिकित्सा कक्ष तैयार रखें।*

बाइक सवार तीन युवकों ने की टाटा प्रवेश के बिजनेस हेड की हत्या, तीनों के दिल्ली में छिपे होने का शक

परिवहन विशेष न्यूज

टाटा स्टील की सहयोगी कंपनी टाटा प्रवेश के इंडिया बिजनेस हेड विनय त्यागी की हत्या मामले में पुलिस ने अब तक डेढ़ सौ से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। जिनके आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि घटना को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया। वहीं बदमाशों के अब तक पकड़े नहीं जाने से नाराज स्वजन ने पुलिस को 48 घंटे का समय दिया है।

साहिबाबाद। टाटा स्टील की सहयोगी कंपनी टाटा प्रवेश के इंडिया बिजनेस हेड विनय त्यागी की उनके घर के पास लूटपाट के बाद हत्या की घटना में पुलिस को बाइक सवार तीन युवकों की तलाश है। आशंका है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये तीनों दिल्ली में छिप गए हैं।

पुलिस को 48 घंटे का दिया समय

पुलिस की टीमें तीनों की तलाश कर रही हैं। पुलिस ने अब तक डेढ़ सौ से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच की है जिनके आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि घटना को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया। वहीं बदमाशों के अब तक पकड़े नहीं जाने से नाराज स्वजन ने पुलिस को 48 घंटे का समय दिया है।

चेतावनी दी है कि इसके बाद सड़क पर उतर कर प्रदर्शन किया जाएगा। पीड़ित परिवार के समर्थन में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ भी सामने आया है। घरों के दरवाजे, खिड़कियां और स्टील का अन्य घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी टाटा प्रवेश के अधिकारी विनय त्यागी शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में परिवार के साथ रहते थे।

शुक्रवार रात की गई हत्या

शुक्रवार रात घर से करीब सात सौ मीटर की दूरी पर उनकी हत्या कर दी गई। बदमाश विनय से डेढ़ लाख रुपये, लैपटाप, मोबाइल फोन और पर्स लूट ले गए। पुलिस ने लूटपाट और हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। इसमें पता लगा कि वह शुक्रवार शाम करीब साढ़े सात बजे वह दिल्ली स्थित अपने आफिस से घर के लिए निकले थे।

रात 8.27 बजे वह गाजियाबाद में राजबाग मेट्रो स्टेशन पहुंचे जहां सीसीटीवी फुटेज में वह दिखाई दिए हैं। इसके बाद रात 11.21 बजे पत्नी को फोन कर उन्होंने अपनी लाइव लोकेशन भेजी और बाद में उसे डिलीट कर दिया।

शराब खरीदने के बाद किया ऑनलाइन पेमेंट

जांच के दौरान पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी। इसमें से एक फुटेज में विनय राजबाग मेट्रो स्टेशन के पास रात करीब साढ़े आठ बजे शराब दुकान पर दिखाई दिए। दुकानदार से पूछताछ में पता लगा कि शराब खरीदने के बाद उन्होंने यूपीआइ के जरिये ऑनलाइन पेमेंट किया।

इसके बाद वह दिल्ली-वजीराबाद रोड की ओर चले गए। उनकी तीन-चार स्थानों पर लोकेशन भी मिली है। अंतिम लोकेशन दिल्ली-वजीराबाद रोड के सर्विस रोड करन गेट पुलिस चौकी के पास की है।

कूलिंग टावर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग
धमाके के साथ 1000 से ज्यादा केमिकल के ड्रम फटे

औद्योगिक क्षेत्र साइट चार स्थित एनवायर्नमेंट इन्फॉर्मेशन बोर्ड पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड फैक्ट्री में रविवार रात साढ़े नौ बजे आग लग गई। फैक्ट्री में हजारों केमिकल से भरे ड्रम रखे थे। देर रात टी ड्रम धमाके के साथ फटते रहे। कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई देती रही। अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी रही।

गाजियाबाद। औद्योगिक क्षेत्र साइट चार स्थित एनवायर्नमेंट इन्फॉर्मेशन बोर्ड पहाड़पुर कूलिंग टावर्स लिमिटेड फैक्ट्री में रविवार रात साढ़े नौ बजे आग लग गई। फैक्ट्री में हजारों केमिकल से भरे ड्रम रखे थे। देर रात टी ड्रम धमाके के साथ फटते रहे। कई किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनाई देती रही। अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी रही। देर रात तक आग में किसी के फंसे होने की पुलिस और अग्निशमन विभाग ने पुष्टि नहीं की।

औद्योगिक क्षेत्र साइट चार की भूखंड संख्या नौ पर फैक्ट्री लगभग 14 एकड़ में बनी है। इस फैक्ट्री में लगभग 700 से ज्यादा लोग काम करते हैं। फैक्ट्री में चार प्लांट लगे हैं। प्लांटो में कूलिंग टावर के अलग-अलग पार्ट्स बनते हैं। फाइबर की सीट भी बनती हैं। फाइबर की सीट भी कूलिंग टावर में लगती है।

फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केमिकल का प्रयोग होता है। रविवार को छुट्टी का दिन होने के कारण फैक्ट्री के तीन प्लांट बंद थे। एक प्लांट में काम चल रहा था। जिस वजह से फैक्ट्री में ज्यादा संख्या में कर्मचारी नहीं थे। आग लगने पर सभी कर्मचारी बाहर आ गए। रविवार रात लगभग 9:30 बजे फैक्ट्री के बंद प्लांट में एक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई।

फैक्ट्री में तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने पहले खुद ही आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन केमिकल और ज्वलनशील समान अधिक मात्रा में होने की वजह से आग बुझाने की बजाय तेजी से फैलती चली गई। इसकी सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई। 20 मिनट बाद अग्निशमन की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझानी शुरू की। देर रात तक आग बुझाने का काम जारी रहा। फैक्ट्री के साइट इंचार्ज संजय गर्ग ने बताया कि आग लगने का कारण नहीं पता पता चला है। अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है।

आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी

फैक्ट्री में ज्वलनशील सामान और केमिकल का इस्तेमाल होने के बाद भी आग बुझाने के इंतजाम नाकाफी थे। फैक्ट्री में आग बुझाने के ठोस इंतजाम नहीं किए गए। यदि आग बुझाने के पुख्ता इंतजाम होते तो तुरंत ही आग पर काबू पाया जा सकता था।

केमिकल पर पानी का हुआ कम असर

फैक्ट्री में बड़ी संख्या में केमिकल से भरे ड्रम रखे हुए हैं। इनमें लग रही आग को बुझाने के लिए अग्निशमन विभाग की टीम में पानी का प्रयोग किया लेकिन केमिकल पर पानी का असर बहुत कम हुआ। जिस वजह से आग बुझाने में मुश्किल हुई।

आग बुझाने में मदद करने के लिए दौड़ पड़े कर्मचारी फैक्ट्री के सामने ही महाराजपुर गांव है। इस गांव में बड़ी संख्या में इस फैक्ट्री में काम करने वाले कामगार रहते हैं। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में कामगार फैक्ट्री पहुंच गए। कामगारों ने आग बुझाने में मदद की। जो सामान जला नहीं था उसे अलग करने के लिए जुट गए। बिना जले सामान को फैक्ट्री से देर रात तक बाहर निकालने का काम जारी रहा।

बिना जले सामान को हटाया गया। आज को फैलने से रोकने के लिए बुलडोजर और अन्य वाहनों में बिना जले सामान को हटाया गया फैक्ट्री से सामान को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। देर रात तक सामान शिफ्ट करने का काम जारी रहा।

क्या होता है कूलिंग टावर

कूलिंग टावर एक विशेष हीट एक्सचेंजर है। इसमें पानी का तापमान कम करने के लिए हवा और पानी को एक दूसरे के सीधे संपर्क में लाया जाता है। ऐसे कुछ पानी वाष्पित हो जाता है। जिससे टावर के माध्यम से प्रसारित होने वाले पानी का तापमान कम हो जाता है।

कैप्टन अजय और राज बब्बर के बीच दूर हुए गिले-शिकवे, बोले- पूरे दिल से करेंगे मदद

गुड़गांव लोकसभा सीट से टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने सोमवार को सारे मतभेद भुलाकर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर के समर्थन का एलान किया है। टिकट मिलने के पांच दिन बाद दोनों एक छत के नीचे आए। इससे पहले कैप्टन किसी भी कार्यक्रम में राज बब्बर के साथ नहीं दिखे थे।

पांच साल तक पसीना बहाया और 400 गांवों में जाकर दौरा किया है। जहां राज बब्बर को उनकी जरूरत होगी, वह पूरी तरह उनके साथ खड़े होंगे। मुझे अब टिकट कटने की चिंता नहीं है।

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। गुड़गांव लोकसभा सीट (Gurgaon Lok Sabha Seat) से टिकट कटने से नाराज चल रहे पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव (Ajay Singh Yadav) ने सोमवार को सारे मतभेद भुलाकर कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर (Raj Babbar) के समर्थन का एलान किया है। टिकट मिलने के पांच दिन बाद दोनों एक छत के नीचे आए। इससे पहले कैप्टन किसी भी कार्यक्रम में राज बब्बर के साथ नहीं दिखे थे।

सोमवार को कांग्रेस प्रत्याशी फिल्म अभिनेता राज बब्बर के समर्थन में कैप्टन अजय सिंह ने झाड़सा स्थित कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की सभा भी बुलाई। सभा के बाद दोनों नेताओं ने एक साथ पत्रकारों को भी संबोधित किया।

कैप्टन के समर्थन से मिली बड़ी ताकत

राज बब्बर ने कहा कि कैप्टन ने साबित कर दिया कि वह नाराज नहीं हैं। उनके साथ जो अचानक हुआ, उससे दुखी थे। उनका नाराज होना स्वाभाविक था। दस सालों से कैप्टन लोगों से जुड़े थे। बब्बर ने कहा कि अगर उन्हें पहले पता होता कि कैप्टन चुनाव लड़ना चाहते हैं तो शायद उनका नाम भी नहीं आता। कैप्टन के समर्थन से आज बहुत बड़ी ताकत मिली है।

क्या बोले कैप्टन अजय

वहीं, कैप्टन अजय ने कहा कि वह चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिला। इस बात की खुशी है कि राज बब्बर लोगों के बीच में जा रहे हैं। उन्होंने भी पांच दिन तक विचार किया। लेकिन आज संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है।

ग्रेटर नोएडा में बीएमडब्ल्यू सवार युवकों की गुंडई, रात में दो किमी पीछा कर महिला की कार पर फेंके पत्थर....

परिवहन विशेष न्यूज

बीटा दो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आईएफएस विला के पास रोडरेज की घटना में सड़क पर जमकर गुंडई हुई। दो कारों की टक्कर होने के बाद एक कार में बैठी महिला को परिवार के साथ अपनी जान बचाना भारी हो गया। आरोपितों ने महिला की कार का दो किलोमीटर तक पीछा किया। उसकी कार के सामने कार लगाकर पत्थर फेंके।

ग्रेटर नोएडा। बीटा दो कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आईएफएस विला के पास रोडरेज की घटना में सड़क पर जमकर गुंडई हुई। दो कारों की टक्कर होने के बाद एक कार में बैठी महिला को परिवार के साथ अपनी जान बचाना भारी हो गया। आरोपितों ने महिला की कार का दो किलोमीटर तक पीछा किया।

ग्रेटर नोएडा में बीएमडब्ल्यू BMW कार सवार युवकों ने रात में महिला की कार का दो किमी तक पीछा किया, उसके बाद फेंके पत्थर...

उसकी कार के सामने कार लगाकर पत्थर फेंके। बैक गीयर में पीड़िता ने कार पीछे की और मौके से भागकर अपनी जान बचाई। दो मई की रात पौने दो बजे हुई घटना का वीडियो सोमवार सुबह इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।

आरोपी BMW कार में थे सवार

घटना का पूरा वीडियो पीड़ित की कार के डेसबोर्ड पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान साकेत भाटी, विपिन चौधरी के रूप में हुई है। दोनों बीएमडब्ल्यू कार में सवार थे। आरोपी बीटेक कर चुके हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।

साइड मिरर से होती है टक्कर

इंटरनेट मीडिया रेडिट व कार इंडिया पेज पर साझा किए गए वीडियो में देखा गया है कि सड़क पर दो कार तेजी से दौड़ रही हैं। एक कार की दूसरी कार से साइड मिरर पर टक्कर होती है। इसके बाद महिला जिस कार में अपने परिवार के साथ सवार थी, उसका आरोपी युवक पीछा करने लगते हैं।

आरोपियों ने कार से पीछा किया शुरू

बीटा दो क्षेत्र से पीछा शुरू कर आरोपियों ने नॉलेज पार्क क्षेत्र तक पीछा किया। आरोपियों से बचने के लिए पीड़िता ने नॉलेज पार्क स्थित पुलिस ऑफिस में घुसने का प्रयास किया, लेकिन गेट बंद था।

ओवरटेक कर कार को रोका

पीड़ितों की आवाज वीडियो में आ रही है, जिसमें महिला कहती है कि वह परिवार के व्यक्ति के इलाज के सिलसिले में अस्पताल जा रहे थे। तभी उनकी कार का पीछा कर उन पर हमला करने की कोशिश की गई। वीडियो में आरोपित युवक पीड़ित की कार पर पत्थर फेंकते देखा गया है। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि बोतल फेंकी गई है। वीडियो में पीड़ित कहते है कि एसएचओ का नंबर मिलाओ जल्दी।

विरासत के सहारे जीत की तलाश करते हुए राहुल गांधी

सुरेश हिंदुस्तानी

कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नामांकन जमा करने के समय जिस प्रकार से बड़े नेताओं का जमघट लगा, वह भले ही जनता में प्रभाव डालने के लिए किया हो, लेकिन इससे यह भी राजनीतिक सन्देश सुनाई दे रहा है कि अब रायबरेली की सीट भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तरप्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव न लड़ पाने की हिम्मत के बाद आखिर परम्परागत रायबरेली से नामांकन दाखित कर दिया। यह बात सही है कि राहुल गांधी के अमेठी छोड़ने के बाद कांग्रेस राजनीति में कोई ठोस सन्देश देने में सफल नहीं हो रही थी, जिसके कारण कांग्रेस के कई नेता अमेठी के बारे में बोलने से किनारा करने लगे थे। अब राहुल गांधी अपने दादा फिरोज खान, दादी इंदिरा गांधी और माँ सोनिया गांधी की विरासत को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। यहाँ सवाल यह नहीं हैं कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस ने रायबरेली को क्यों चुना, बल्कि सवाल यह है कि राहुल गांधी ने अमेठी को क्यों छोड़ा। क्या वास्तव में राहुल गांधी को फिर से अपनी पराजय का डर लगने लगा था? अगर यह सही है तो फिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी हर बार अपने लिए सुरक्षित स्थान की तलाश क्यों करते हैं। उल्लेखनीय है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमेठी में अपनी ज़मीन खिसकती दिखाई दी, तब उन्होंने एकदम सुरक्षित लगने वाली सीट केरल की वायनाड को चुना। वहाँ से चुनाव जीते जरूर, लेकिन अमेठी की हार कांग्रेस परिवार की हार थीं, जिसे कांग्रेस आज तक भुला नहीं पायी है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाना खतरे से खाली नहीं था।

कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के नामांकन जमा करने के समय जिस प्रकार से बड़े नेताओं का जमघट लगा, वह भले ही जनता में प्रभाव डालने के लिए किया हो, लेकिन इससे यह भी राजनीतिक सन्देश सुनाई दे रहा है कि अब रायबरेली की सीट भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। यह इसलिए भी कहा जा सकता है कि वहाँ लगभग सभी बड़े नेता उपस्थित हुए। यहाँ तक कि प्रियंका वाड्रा के पति रोबर्ट वाड्रा भी कांग्रेस के विरासती राजनेता के तौर पर उपस्थित हुए। ऐसे में एक सवाल यह भी आता है कि एक ही परिवार के चार व्यक्तियों को कांग्रेस के बड़े नेताओं के रूप में प्रचारित करना निसंदेह कांग्रेस

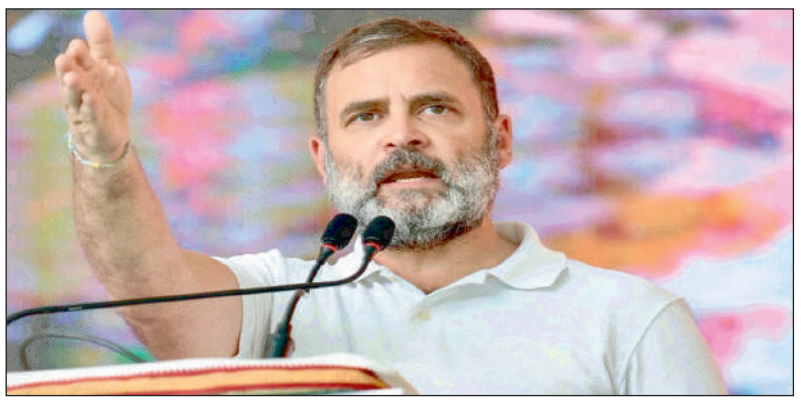

पर परिवारवादी होने को ही प्रमाणित करता है। जिस परिवारवाद के आरोप के कारण कांग्रेस असहज हो जाती है, आज कांग्रेस ने फिर से उसी रास्ते पर कदम बढ़ाने को अपनी नियति मान लिया है। हालांकि कांग्रेस ने आनन फानन में राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाकर यह तो सन्देश दिया ही है कि भारत में रायबरेली ही राहुल गांधी के लिए सबसे सुरक्षित लोकसभा सीट है। यहाँ कांग्रेस का परम्परागत मतदाता है, वहीं यह क्षेत्र नेहरू गांधी परिवार की विरासत भी है। कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर अपनी विरासत को विस्मृत कर देता है, तो उसे नए सिरे से अपनी ज़मीन तैयार करनी पड़ती है। और अगर विरासत के आधार पर अपने कदम बढ़ाता है तो उसकी आधी राह आसान हो जाती है। राहुल गांधी के सामने तमाम सवाल होने के बाद भी ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी आधी बाधा को पार कर लिया है। रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ इसलिए भी माना जाता है कि क्योंकि यहाँ से इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान दो बार सांसद रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी भी सांसद रहीं। अब पिछले पांच बार से सोनिया गांधी लोकसभा का चुनाव जीती हैं। मजेदार बात यह भी है कि वर्ष 1977 के आम चुनाव में जनता लहर में इंदिरा गांधी को भी पराजय का दंश भोगना पड़ा। उसके बाद एक बार भाजपा ने भी परचम लहराया है। इसलिए यह कहा जाना कि रायबरेली में कांग्रेस आसानी से विजय प्राप्त करेंगी, कठिन ही है। आज कांग्रेस की स्थिति देखकर यह भी कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि आज की कांग्रेस के पास इंदिरा गांधी जैसा नेता नहीं है। ज़ब इंदिरा गांधी चुनाव हार सकती हैं, तब आज तो कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है। ऐसा तो तब हुआ, ज़ब उत्तरप्रदेश में समाज़वादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था, इसलिए कांग्रेस उत्तरप्रदेश में अच्छी खासी जीत हासिल करती थी। लेकिन अब उत्तरप्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। अब कांग्रेस के पास पहले जैसा वोट बैंक भी नहीं है, हालांकि इस चुनाव में सपा का समर्थन कांग्रेस के पास है, इसलिए चुनाव में सपा के कार्यकर्ता भी राहुल का प्रचार करेंगे, ऐसे में निश्चित ही कांग्रेस का वजूद बढेगा ही, यह तय है, लेकिन कितना बढ़ेगा, यह कहने में जल्दबाजी ही होगी।

वर्तमान में कांग्रेस के लिए यह पेचीदा सवाल ही था कि कांग्रेस की ओर से अमेठी और रायबरेली से किसको प्रत्याशी घोषित किया जाए, क्योंकि इन दोनों सीटों पर प्रथम तो गांधी परिवार का पुख्ता दावा बनता था। इसलिए दोनों क्षेत्रों में से किसी एक से प्रियंका वाड्रा को चुनाव मैदान में उतारने की क़वायद भी की जा रही थी, लेकिन प्रियंका को इस बार चुनाव लड़ने से दूर कर दिया। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के रायबरेली से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस अमेठी के चुनाव को गंभीरता से लेगी, क्योंकि अब कांग्रेस का पूरा जोर राहुल गांधी को जिताने में लगेगा। राहुल गांधी को जिताना कांग्रेस की मज़बूरी है, क्योंकि अब राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस की साख दांव पर लगी है। अगर कांग्रेस रायबरेली से चुनाव हारती है तो देश में कांग्रेस के बारे में गलत सन्देश जाऐगा। यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आ रहा है कि राहुल गांधी द्वारा पिछले चुनाव में भी दो स्थानों से चुनाव लड़े थे, जिसमें अमेठी में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब वायनाड से उम्मीदवारी के बाद रायबरेली की रुख करके फिर से संदेह को जन्म दिया है। ऐसा लग रहा है कि इस बार वायनाड का चुनाव बहुत ही टक्कर का माना जा रहा है। कुछ खबरें तो राहुल गांधी के हारने तक की बात कह रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए ही राहुल गांधी को फिर से दो स्थानों से चुनाव लड़ाया जा रहा है। राहुल गांधी का उत्तरप्रदेश से चुनाव लड़ना कोई नया नहीं है, वे अमेठी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। इसलिए उनके नाम का जादू कोई नया प्रभाव छोड़ेगा, यह पूरी तरह विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता।

हुंडई क्रेटा के दीवाने हो रहे लोग, अप्रैल 2024 में हुंडई को मिले इस गाड़ी के लिए सबसे अधिक ऑर्डर

परिवहन विशेष न्यूज

अप्रैल 2024 में हुंडई को Creta के लिए सबसे अधिक ऑर्डर मिले हैं। हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ तरुण गर्ग ने कहा कि हुंडई क्रेटा को लोग जमकर पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि हुंडई की बिक्री में सबसे अधिक योगदान इसी गाड़ी का है। कंपनी ने घरेलू मार्केट में साल-दर-साल 12 .5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

नई दिल्ली। जनवरी 2024 में Hyundai Creta facelift की बिक्री शुरू हुई थी। बिक्री शुरू होने के बाद हुंडई ने इस गाड़ी की हर महीने औसतन 15,000 हजार यूनिट्स की बिक्री की है। जबकि अप्रैल में बिक्री का आंकड़ा 15,447 यूनिट्स का रहा था।

कंपनी का कहना है उसके कुल ऑर्डर्स में से 50 प्रतिशत बुकिंग केवल हुंडई क्रेटा के लिए हुई है। हुंडई के मुताबिक, मिडसाइज एसयूवी फेसलिफ्ट वर्जन के लॉन्च होने के करीब 1 लाख ऑर्डर मिले हैं।

खूब पसंद की जा रही हुंडई क्रेटा

हुंडई मोटर इंडिया के सीओओ, तरुण गर्ग ने कहा कि हुंडई क्रेटा को लोग जमकर पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि हुंडई की बिक्री में सबसे अधिक योगदान इसी गाड़ी का है। कंपनी ने घरेलू मार्केट में साल-दर-साल 12.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

हुंडई ने यह भी घोषणा की कि अप्रैल 2024 में बेची गई यूनिट्स में क्रेटा की हिस्सेदारी 15,447 यूनिट्स के साथ सबसे अधिक रही है। वेन्यू की 9,122 यूनिट्स, जबकि एक्सटर की बिक्री 7,756 यूनिट्स रही। इसके अलावा हुंडई इंडिया ने ये भी बताया कि शहरी और सेमी अर्बन इलाकों में एसयूवी मांग अच्छी देखने को मिल रही है।

हुंडई की प्रमुख एसयूवी क्रेटा, वेन्यू, एक्सटर और अलकजार को इन इलाकों में खूब पसंद किया जा रहा है। जबकि हुंडई मोटर इंडिया वर्तमान में 43,000 इकाइयों जल्द डिलीवरी करने वाली है। कंपनी का कहा कि भले ही हमें अधिक ऑर्डर मिल रहे हैं लेकिन, हम डिलीवरी को पूरी तरह से आश्वस्त हैं।

Hyundai Creta 2024 इंजन

Hyundai Creta 2024 तीन इंजन विकल्प- 1.5l PL, 1.5l DSL, 1.5l Turbo पेट्रोल में पेश की जाती है। इसका 1.5 पेट्रोल टर्बो इंजन 5,500 rpm पर 160 पीएस की शक्ति और 253 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है। गाड़ी सेफ्टी फीचर्स का खास ख्याल रखा गया है। इसमें 19 सेफ्टी फीचर्स के साथ लेवल 2-एडास मिलता है।

2024 Hyundai Creta कुल 7 ट्रिम लेवल में उपलब्ध है। इसमें ई, ईएक्स, एस, एस (ओ), एसएक्स, एसएक्स टेक और एसएक्स (ओ) शामिल है। इसके रंग विकल्पों में 6 सिंगल-टोन शेड्स और एक टू-टोन शेड का चयन शामिल है। लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स) तकनीक का आगमन एक महत्वपूर्ण आकर्षण के रूप में सामने आया है, जो कुल 19 सहायक और सुरक्षा सुविधाएं प्रदान करता है।

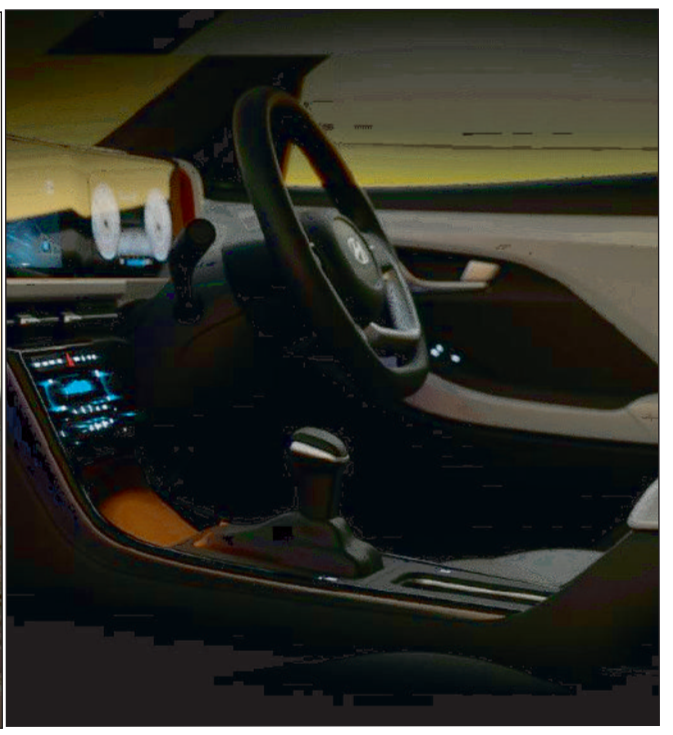

लॉन्च होने से पहले नजर आई सिट्रोएन की कूपे एसयूवी बेसाल्ट, जानें क्या सामने आई जानकारी

फ्रेंच कार निर्माता Citroen की ओर से जल्द ही नई एसयूवी Basalt को भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च से पहले कंपनी की नई एसयूवी को भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाड़ी में किस तरह के फीचर्स और इंजन को दिया जा सकता है। इसे कब तक लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। Citroen की ओर से जल्द ही कूपे SUV के तौर पर नई गाड़ी को पेश किया जाएगा। कंपनी की ओर से Basalt कूपे SUV को पेश किए जाने से पहले टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि गाड़ी से जुड़ी क्या जानकारियां सामने आई हैं और कंपनी की ओर से इसे कब तक लॉन्च किया जा सकता है।

नजर आई Citroen Basalt कूपे SUV

सिट्रॉएन की ओर से बेसाल्ट कूपे एसयूवी को भारत में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्च से पहले इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। टेस्टिंग के दौरान देखी गई यूनिट प्रोडक्शन के काफी नजदीक है और इससे गाड़ी के डिजाइन और फीचर्स की काफी जानकारी मिल रही है। हाल में टेस्ट के दौरान स्पॉट की गई यूनिट बिना कैमोफ्लाज के स्पॉट की गई है।

क्या मिली जानकारी

सिट्रॉएन बेसाल्ट कूपे एसयूवी के जिस मॉडल को स्पॉट किया गया है। वह इसका मिड वेरिएंट हो सकता है, क्योंकि इसमें अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलाइट जैसे फीचर्स गायब हैं। वहीं इसके टॉप वेरिएंट में कंपनी इनके साथ ही कई और बेहतरीन फीचर्स को दे सकती है। इसका डिजाइन भी सिट्रॉएन की अन्य कारों की तरह ही है। सामने से यह कंपनी की सी3 एयरक्रॉस की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें कूपे की तरह रूफलाइन भी दी गई है।

कहां होगी पोजिशन

कंपनी की ओर से फिलहाल भारतीय बाजार में आईसीई के साथ सी3 और सी3 एयरक्रॉस के अलावा सी5 एयरक्रॉस को ऑफर किया जाता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बेसाल्ट कूपे एसयूवी को कंपनी सी3 एयरक्रॉस के ऊपर पोजिशन करेगी और इसमें कई ऐसे फीचर्स को भी दिया जा सकता है, जिनको फिलहाल सी3 एयरक्रॉस में ऑफर किया जाता है।

कितना दमदार इंजन

रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से इस गाड़ी में भी 1.2 लीटर का तीन सिलेंडर इंजन दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें टर्बो इंजन का विकल्प भी मिल सकता है। जिससे एसयूवी के मैनुअल वेरिएंट को 110 पीएस की पावर के साथ 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। वहीं छह स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट से 110 पीएस की पावर और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल सकता है। उम्मीद है कि कंपनी इस नई गाड़ी को इस साल जून और सितंबर के बीच पेश कर सकती है।

Maruti Jimny से लेकर XL6 पर May 2024 में मिल रहा हजारों रुपये बचाने का मौका, जानें किस पर क्या है ऑफर

नई दिल्ली। May 2024 में अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी Nexa की कई कारों पर कंपनी की ओर से डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से किस कार पर कितना डिस्काउंट कंपनी की ओर से ऑफर किया जा रहा है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Maruti Baleno

मई 2024 में मारुति अपनी की बलेनो पर सबसे ज्यादा ऑफर दिए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से इस महीने में हैचबैक को खरीदने पर 50 हजार रुपये तक का फायदा उठाया जा सकता है। मारुति बलेनो की एक्स शोरूम कीमत 6.66 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

Maruti Jimny

मारुति की ऑफ रोडिंग एसयूवी के तौर पर आने वाली जिम्नी पर भी मई महीने में 50 हजार रुपये बचाए जा सकते हैं। कंपनी की इस एसयूवी को 12.74 लाख रुपये की शुरूआती एक्स शोरूम कीमत पर खरीदा जा सकता है।

Maruti Ciaz

मारुति की मिड साइज सेडान कार सियाज की एक्स शोरूम कीमत 9.40 लाख रुपये से शुरू होती है। इस कार को मई 2024 में खरीदने पर अधिकतम 48 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं।

Maruti Xl6

कंपनी की लग्जरी एमपीवी के तौर पर आने वाली X16 पर मई 2024 में 20 हजार रुपये की छूट मिल रही है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 11.61 लाख रुपये से शुरू हो जाती है।

Maruti Fronx

मारुति की एक और एसयूवी Fronx को मई 2024 में खरीदना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इस एसयूवी पर कंपनी इस महीने में 28 हजार रुपये के ऑफर्स दे रही है। इसके टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर 43 हजार रुपये

Bajaj की पहली CNG Bike का डिजाइन लॉन्च से पहले हुआ लीक, जानें कहां लगेगा सिलेंडर

देश की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता Bajaj जल्द ही पहली CNG Bike को भारतीय बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है। लेकिन लॉन्च से पहले ही बाइक के डिजाइन की जानकारी सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। लीक हुए डिजाइन में बाइक और सीएनजी सिलेंडर के बारे में क्या जानकारी मिल रही है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश की प्रमुख दो पहिया वाहन निर्माता Bajaj जल्द ही पहली CNG Bike को भारतीय बाजार में पेश करने की तैयारी कर रही है। Bajaj की ओर से जल्द ही देश की पहली CNG Bike को लॉन्च किया जाएगा। बाइक के लॉन्च से पहले इसके डिजाइन की जानकारी सोशल मीडिया पर लीक हो गई है। जिसमें इसकी भी जानकारी मिल रही है कि बाइक में सीएनजी सिलेंडर किस जगह लगाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइक की और क्या जानकारी मिली है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पहली CNG Bike की डिटेल हुई लीक

बजाज की ओर से जल्द लॉन्च होने वाली देश की पहली CNG Bike के डिजाइन की जानकारी लॉन्च से पहले ही लीक हो गई है। लीक हुए ब्लूप्रिंट में बाइक की चेसिस, सीएनजी और पेट्रोल टैंक की जानकारी सामने आई है।

कैसा होगा डिजाइन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीक हुई जानकारी से यह पता चल रहा है कि बाइक में डबल क्रैडल फ्रेम को दिया जा सकता है जिसके साथ सिलेंडर को रोकने के लिए ब्रेसिस लगे होंगे। बाइक में सीएनजी के सिलेंडर को सीट के नीचे की ओर दिया जा सकता है। वहीं सीएनजी भरने के लिए नोजल को सामने की ओर दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक छोटा पेट्रोल टैंक भी दिया जाएगा। बाइक में पेट्रोल भरने की जगह अन्य बाइक्स की तरह ही होगी। बाइक में स्लोपर इंजन को दिया जा सकता है, जिसको पेट्रोल और सीएनजी से चलाया जा सकेगा।

लॉन्च से पहले हो रही टेस्टिंग

बजाज की ओर से सीएनजी बाइक को लॉन्च करने से पहले टेस्ट किया जा रहा है। टेस्टिंग के दौरान ही इस बाइक को कई बार देखा जा चुका है। टेस्टिंग बाइक को टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रियर में मोनोशॉक, डिस्क और ड्रम ब्रेक सेटअप के साथ देखा गया था। सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के लिए बाइक सिंगल-चैनल एबीएस या कॉम्बी-ब्रेकिंग से लैस हो सकती है।

कितनी क्षमता की होगी बाइक

कंपनी की ओर से अभी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइक को 125 सीसी सेगमेंट में लाया जा सकता है। इस बाइक के अलावा कंपनी की योजना 2025 तक पांच से छह सीएनजी बाइक्स को भारतीय बाजार में लॉन्च करने की है। बाइक को 18 जून 2024 को लॉन्च किया जा सकता है। इसका संभावित नाम ब्रूजर हो सकता है।

मई 2024 में टोयोटा की किस गाड़ी के लिए करना होगा लंबा इंतजार, जानें किस पर कितना है वेटिंग पीरियड

जापानी कार निर्माता Toyota की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन हैचबैक एमपीवी और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से ऑफर की जाने वाली इनोवा फॉर्च्यूनर अर्बन क्रूजर हैदराबाद रुमियन हिलक्स वेलफायर और Glanza गाड़ी को अगर इस May 2024 में बुक करवाया जाता है तो डिलीवरी के लिए कितना इंतजार (Waiting Period) करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में Toyota की ओर से कई बेहतरीन कारों को ऑफर किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की कुछ कारों को इस महीने में खरीदने पर कितना इंतजार करना पड़ सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Toyota Fortuner

टोयोटा की ओर से भारत में फुल साइज एसयूवी सेगमेंट में फॉर्च्यूनर को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस दमदार एसयूवी को देश में काफी ज्यादा पसंद भी किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने इस एसयूवी को बुक करवाया जाता है, तो इसके कुछ वेरिएंट्स की डिलीवरी मिलने में दो महीने तक का समय लग सकता है। इससे पहले यह अवधि करीब तीन महीने की थी।

Toyota Innova Hycross

टोयोटा की ओर से इनोवा हाईक्रॉस को लग्जरी एमपीवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस एमपीवी की बाजार में काफी ज्यादा मांग रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनोवा हाईक्रॉस पर करीब 14 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। कई जगहों पर इसे घर लाने के लिए इससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले अप्रैल में इस गाड़ी के लिए वेटिंग पीरियड करीब 12 महीने था।

Toyota Innova Crysta

टोयोटा की ओर से इनोवा क्रिस्टा को भी डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जाता है। हाईक्रॉस के साथ ही इस एमपीवी की भी बाजार में काफी ज्यादा मांग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एमपीवी पर भी पांच महीने तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है।

Toyota Urban Cruiser Hyryder

टोयोटा की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अर्बन क्रूजर हाईराइडर को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। कंपनी इस एसयूवी को हाइब्रिड तकनीक के साथ भी ऑफर करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के कुछ वेरिएंट्स को खरीदकर घर लाने के लिए छह महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले इसके लिए करीब आठ महीने तक वेटिंग पीरियड था। इसके सीएनजी वेरिएंट पर पांच महीने और हाइब्रिड वेरिएंट पर करीब दो महीने का वेटिंग पीरियड है।

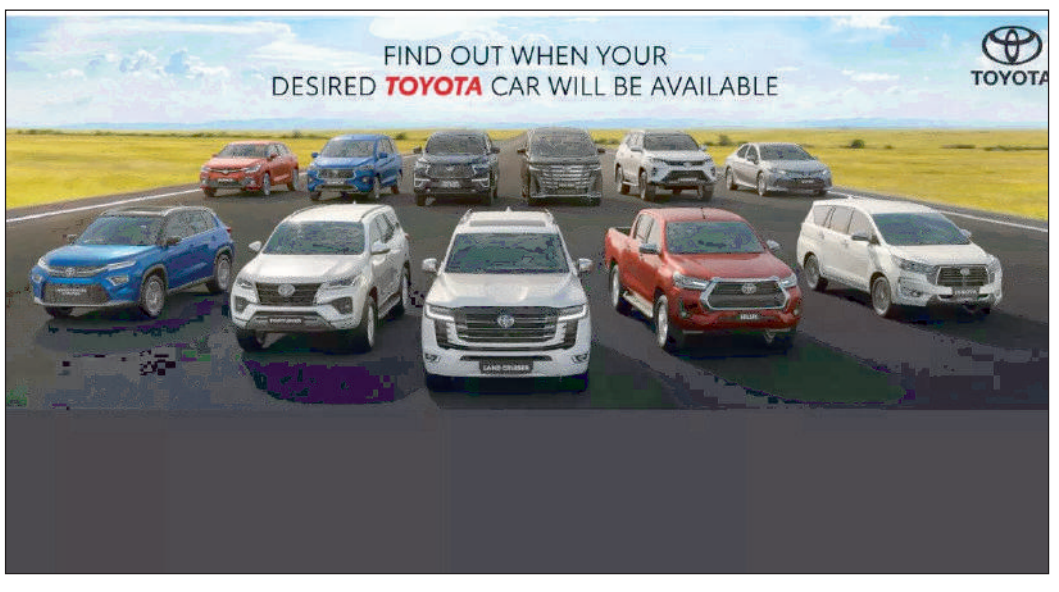

Toyota Glanza

टोयोटा की ओर से हैचबैक कार के तौर पर ग्लैंजा को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी को पेट्रोल के साथ ही सीएनजी तकनीक के साथ भी लाया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस कार को खरीदने के लिए सबसे कम इंतजार करना पड़ रहा है। टोयोटा ग्लैंजा को सिर्फ एक महीने में घर लाया जा सकता है।

Toyota Rumion

टोयोटा और मारुति की साझेदारी के बाद बजट एमपीवी Rumion को टोयोटा की ओर से ऑफर किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस एमपीवी के सामान्य वेरिएंट्स पर तीन महीने और सीएनजी वेरिएंट पर करीब दो महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

Toyota Velfire

टोयोटा की ओर से लग्जरी एमपीवी के तौर पर वेलफायर को ऑफर किया जाता है। इस एमपीवी पर भी करीब 12 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है।

Toyota Hilux और Camry के लिए कितना इंतजार

टोयोटा के लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक Hilux और लग्जरी सेडान कार Camry पर भी मई में करीब एक महीने की वेटिंग चल रही है। हालांकि इन सभी पर शहर और शोरूम के मुताबिक वेटिंग पीरियड अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए गाड़ी खरीदने से पहले शोरूम से सही वेटिंग पीरियड की जानकारी ली जा सकती है।

14 नए फीचर्स के साथ आया टोयोटा इनोवा क्रिस्टा GX+ वेरिएंट, जानें कितनी है कीमत

जापानी वाहन निर्माता Toyota की ओर से भारतीय बाजार में कई बेहतरीन कारों और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से हाल में ही एमपीवी सेगमेंट में Innova Crysta के नए वेरिएंट को लॉन्च किया है। इसमें 14 नए फीचर्स को भी दिया गया है। Toyota Innova Crysta के GX+ वेरिएंट को किस कीमत पर लाया गया है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। Toyota की ओर से भारतीय बाजार में Innova Crysta के नए वेरिएंट को लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी की ओर से इसके नए वेरिएंट में किन नए फीचर्स को दिया है। इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Toyota ने लॉन्च किया Innova Crysta GX+ वेरिएंट

टोयोटा की ओर से एमपीवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी Innova Crysta का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी की ओर से भारतीय बाजार में इस गाड़ी के नए वेरिएंट के तौर पर GX+ को लाया गया है। इसमें कंपनी ने कई नए फीचर्स को जोड़ा है। जिससे सफर के दौरान आसानी होगी।

कैसे हैं फीचर्स

Toyota Innova Crysta GX+ में कंपनी की ओर से जिन फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है उनमें रियर कैमरा, ऑटो फोल्ड मिरर्स, डीवीआर, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, वुडन पैनल, प्रीमियम फैब्रिक सीटें, सात और आठ सीटों का विकल्प शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें पांच नए रंगों को भी दिया गया है, जिसमें Super White, Attitude Black Mica, Avant-Garde Bronze Metallic, Platinum White Pearl and Silver Metallic शामिल हैं।

कितना दमदार इंजन

कंपनी की ओर से जानकारी दी गई है कि इस नए वेरिएंट में 2.4 लीटर का डीजल इंजन दिया जाएगा। जिसके साथ पांच स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन होगा। ड्राइविंग के लिए इसमें ईको और पावर मोड को भी दिया गया है। इस वेरिएंट के साथ ही इनोवा क्रिस्टा के पांच ग्रेड डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएंगे।

भारत 2047 तक ऐसे बनेगा विकसित देश

डा. जयंती लाल भंडारी

निश्चित रूप से भारत को विकसित देश बनाने के लिए वर्तमान विकास मॉडल में सुधार करना होगा। विकास मॉडल में समृद्ध भारत के साथ समावेशी भारत की तस्वीर को हरदम सामने रखना होगा।

निश्चित रूप से भारत को विकसित देश बनाने के लिए वर्तमान विकास मॉडल में सुधार करना होगा। विकास मॉडल में समृद्ध भारत के साथ समावेशी भारत की तस्वीर को हरदम सामने रखना होगा। जहां देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ाते रहना होगा, वहीं रोजगार वृद्धि व आम आदमी के सशक्तिकरण के अधिक प्रयास करने होंगे'

इन दिनों पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अर्थ विशेषज्ञ एकमत से टिप्पणी कर रहे हैं कि यदि भारत अपने विकास मॉडल में तेज विकास के साथ समावेशी विकास तथा रोजगार एवं साझी समृद्धि की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ेगा, तो भारत वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के सपने को साकार कर सकेगा। गौरतलब है कि इस समय दुनिया में कोई 40 ही देश विकसित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विकसित यूरोपीय देश हैं। भारत इस समय विकासशील देश है। अब भारत के विकसित राष्ट्र बनने की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होने की संभावनाओं के कई आधार हैं। भारत दुनिया में वैश्विक सुस्ती की चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास की डगर पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में 26 अप्रैल को प्रकाशित वैश्विक परामर्श एजेंसी डेलॉयट इंडिया की नई रिपोर्ट के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.6 से 7.8 प्रतिशत कर दिया है। कहा गया है कि भारत में मध्यम आय वर्ग के लोगों की संख्या में तेज वृद्धि से क्रय शक्ति बढ़ी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2 साल से वृद्धि के मजबूत आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था को कोविड के पहले के स्तर में आने में मदद की है।

बुनियादी ढांचे पर सरकार के व्यय में तेजी से निवेश को समर्थन मिला है। इससे भारत को वृद्धि की रफ्तार तेज रखने में मदद मिली है। निस्संदेह यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है, जब कुछ दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मजबूत घरेलू मांग और कामकाज करने वाली आबादी को देखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत का वृद्धि अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि का अनुमान 6.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। निश्चित रूप से विकसित भारत बनने के लिए भारत की मुट्ठियों में कई महत्त्वपूर्ण

संभावनाएं हैं। भारत में पिछले वर्ष 2023 में आयोजित जी-20 के शानदार सफल आयोजन से भारत के पास विकास के नए सूत्र आए हैं। भारत के पास पिछले 10 वर्षों की शानदार विरासत है। यह भारत का ऐसा समय है जब हमारी आर्थिक वृद्धि लगातार बढ़ रही है। भारत में स्थिति मैन्युफेक्चरिंग, निवेश और निर्यात के मद्देनजर उपयुक्त है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से देश तेजी से आगे बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ा है। वैश्विक सुस्ती के बीच भारत का शेयर बाजार नई ऊंचाइयों पर है। पिछले एक दशक में हुए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म देश के विकास के लिए गेमचेंजर रहे हैं।

भारत में अहम आर्थिक सुधार हुए और इन सुधारों में जन धन, आधार और मोबाइल आधारित सब्सिडी सुधार (जेएएम) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) प्रमुख हैं। निस्संदेह इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत को विशेष अहमियत दी जा रही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थाई सदस्य देश बनाने के लिए अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का समर्थन रेखांकित हो रहा है और भारत वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका के लिए तैयार है। भारत के तेजी से बढ़े कृषि क्षेत्र से दुनिया की उम्मीदें बढ़ गई हैं। तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार के कारण भारत के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) बढ़ रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के द्वारा लगातार भारत की ओर अधिक रेमिटेंस भेजा जा रहा है। इस समय देश के वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा तथा नए तकनीकी विकास के कारण आर्थिक विकास को गति मिल रही है चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के मद्देनजर भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरकर सामने आया है। अब भारत में लॉजिस्टिक लागत में कमी आने लगी है।

इतना ही नहीं भारत दुनिया के 85 देशों को हथियार व सैन्य सामग्रियों का निर्यात भी कर रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरकार के द्वारा विगत 10 वर्षों में किए गए आर्थिक और वित्तीय सुधारों के साथ-साथ कठोर प्रशासनिक निर्णयों से देश में आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ी है। इसके साथ-साथ दुनिया में मजबूत लोकतंत्र और स्थिर सरकार के रूप में भारत की पहचान, स्टार्टअप का दुनिया में सबसे तेजी से बढना, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के लिए बढ़ते हुए नए दौर के कौशल निर्माण कार्यक्रम, बड़े पैमाने पर पूंजीगत खर्च, गैर जरूरी आयात में कटौती, खेलों के क्षेत्र में भारत की लंबी छलांगों से लाभान्वित होती भारतीय अर्थव्यवस्था और बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता देश के टिकाऊ विकास की बुनियाद बन गई है। निश्चित रूप से भारत को विकसित देश बनाने के लिए वर्तमान विकास मॉडल में सुधार करना होगा। विकास मॉडल में समृद्ध भारत के साथ समावेशी भारत की तस्वीर को हरदम सामने रखना होगा। जहां देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ाते रहना होगा, वहीं रोजगार वृद्धि व आम आदमी के सशक्तिकरण के अधिक प्रयास करने होंगे। यद्यपि पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबों में बड़ी कमी आई है। लेकिन अब बकाया 15 करोड़ से अधिक गरीबों को नई मुस्कराहट देने का जोरदार अभियान आगे बढ़ाना होगा। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि देश के आम आदमी के कमजोर जीवन स्तर को अच्छे जीवन स्तर में बदला जाए। देश में 19 करोड़ से अधिक महिलाओं को पेड वर्कफोर्स में शामिल करने की रणनीति को अमलीजामा पहनाना होगा। हमें विकास के लिए चीन की कम कौशल वाले विनिर्माण की नीति को अपनाने की बजाय हमारे शक्तिशाली सर्विस सेक्टर के जरिए विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढना होगा। कई अहम सुधारों को वैधानिक बनाते हुए उनका तेजी से क्रियान्वयन करना होगा। कृषि, श्रमिक, भूमि भ्रष्टाचार के उन्मूलन और अन्य सुधारों की डगर पर तेजी से बढना होगा।

यद्यपि केंद्र सरकार 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में तबदील करने की महत्त्वाकांक्षी योजना को आकार देने में सफल रही है, लेकिन ये अब तक लागू नहीं हुई है। अब एक ऐसे समय में जब कई देशों की कंपनियां चीन से बड़ी संख्या में उद्योग-कारोबार स्थानांतरित करते हुए दिखाई दे रही हैं तब हम अच्छे श्रम कानूनों से इसका लाभ उठा सकते हैं। देश के तेज विकास के लिए उभरते क्षेत्रों में शोध एवं विकास क्षेत्र में जरूरी निवेश पर्याप्त नहीं है। शोध एवं विकास के क्षेत्र में भारत का प्रति व्यक्ति व्यय दुनिया में विभिन्न तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। निश्चित रूप से देश को विकसित देश बनाने की संभावनाओं को साकार करने के लिए इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से जून 2024 में गठित होने वाली सरकार स्थिर और मजबूत होना जरूरी है। देश को एक ऐसी प्रभावी और त्वरित प्रशासनिक निर्णय लेकर उन्हें कार्यान्वित करने वाली क्षमतावान सरकार की जरूरत है, जो 2047 तक भारत को दुनिया का विकसित देश बनाने के मद्देनजर 8.9 फीसदी सालाना विकास दर प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्रति व्यक्ति आय को पांच गुना तक करके 12 हजार डॉलर की ऊंचाई पर पहुंचाने, मजबूत आर्थिक सुधारों, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं व राष्ट्रीय विकास के मूल्यों के साथ विकास का जज्बा पैदा करते हुए देश को रणनीतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ाए।

संपादक की कलम से

शहजादे बनाम शहंशाह

प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए 'शहजादे' सांकेतिक शब्द का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस श्रेणी में अब उन्होंने तेजस्वी यादव को भी 'बिहार का शहजादा' करार दिया है। चुनाव आयोग को इन सांकेतिक शब्दों पर आपत्ति क्यों नहीं है अथवा ये शब्द आचार संहिता का उल्लंघन किस तरह नहीं करते हैं, इसका स्पष्टीकरण तो चुनाव आयोग ही देगा। अलबत्ता देश हैरान हो सकता है कि क्या इन शब्दों पर भी जनादेश मांगा या दिया जा सकता है? 'शहजादे' की प्रतिक्रिया में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को 'शहंशाह' करार दिया है। उन्होंने पलटवार की भाषा में कहा है कि वे उनके भाई को 'शहजादा' बुलाते हैं। उस 'शहजादे' ने ही कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। 'शहजादे' ने भाइयों, बहनों, किसानों और मजदूरों से उनकी तकलीफें, समस्याएं पूछी हैं तथा यह भी जानने की कोशिश की है कि उन्हें कैसे हल किया जा सकता है? प्रियंका ने प्रधानमंत्री पर हमला भी किया है कि वह तो महलों में रहते हैं। उन्हें देश के आम आदमी की मुश्किलों का एहसास कैसे होगा? लोकतंत्र में 'शहजादे' और 'शहंशाह' की कोई गुंजाइश नहीं है। दरअसल सवाल है कि आम चुनाव की सियासत इन सांकेतिक शब्दों पर क्यों आ गई? शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने ही की और फिर भाजपा के अन्य प्रचारक नेता भी व्यंग्य कसने लगे। मोदी को इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? उनके पक्ष में ऐसा 10-साला जनादेश रहा है, उसकी स्थिरता और विकास के मुद्दे आज कहां हैं?

क्या प्रधानमंत्री चुनाव को अब 'मोदी बनाम राहुल गांधी' बना रहे हैं? क्या सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बजाय प्रधानमंत्री मोदी चुनाव को अपने ही इर्द-गिर्द केंद्रित कर देना चाहते हैं? क्या वह कांग्रेस की जातीय जनगणना और मुस्लिम आरक्षण का मुकाबला हिंदू धर्म की राजनीति से करना चाहते हैं? क्या चुनावी एजेंडा कांग्रेस तय करेगी और भाजपा उसकी प्रतिक्रिया में अपना चुनाव प्रचार जारी रखेगी? प्रधानमंत्री 2002 के गोधरा कांड सरीखे पुराने मुद्दों को सतह पर लाकर अतीत के आधार पर नया जनादेश मांगना चाहते हैं? 2014 और 2019 के आम चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा-एनडीए ने तत्कालीन और प्रासंगिक मुद्दों पर ही लड़े थे और शानदार जनादेश हासिल किए थे। इस बार भी जनादेश को लेकर कोई संशय नहीं है। आंकड़े कम हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से जिन मुद्दों पर चुनाव लडने की अपेक्षाएं थीं, वे गौण हैं या हाशिए पर सरका दिए गए हैं। फोकस 'शहजादे' और उनकी सियासत पर है। यकीनन प्रधानमंत्री मोदी भाजपा-एनडीए के लिए आज भी 'तुरुप का पत्ता' हैं, लेकिन ऐसे आकलन सामने आए हैं कि जब भी वह 'शहजादे' शब्द बोलते हैं, तो वोट बढ़ जाते है। 'शहजादा' कहने से बात मुस्लिम बादशाहत से जुड़ती है और हिंदू-मुस्लिम मुद्दा भाजपा को ताकत और धुरवीकरण देता है।

बेशक प्रधानमंत्री की निजी, पारिवारिक पृष्ठभूमि 'गरीबी' की रही है, लेकिन बार-बार उसका राग अलापने से सहानुभूति मिलेगी, हमें तो ऐसा नहीं लगता। अब उल्लेख उनके कामों और नीतियों का होना चाहिए, जिनकी बदौलत उन्होंने देश में लाभार्थियों की एक खास जमात बना दी है। निश्चित तौर पर वे मोदी-भाजपा के समर्थक होंगे। दरअसल कांग्रेस इतनी मजबूत भी नहीं है और 300 से कुछ ज्यादा सीटों पर ही उसने उम्मीदवार खड़े किए हैं, कांग्रेस में ही पार्टी छोडने वालों की भगदड़ मची है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी को निजी, आक्रामक, सांकेतिक शब्दों की राजनीति करनी पड़ रही है, हमारी समझ के बाहर है। बीते दिनों सीएसडीएस का एक सर्वे सामने आया था, जिसमें अयोध्या के राम मंदिर को 7-8 फीसदी वोट मिले थे, जबकि 27 फीसदी से अधिक ने महंगाई और 23 फीसदी से अधिक लोगों ने बेरोजगारी को बुनियादी मुद्दा या समस्या माना था। क्या ऐसे ही कारणों से प्रधानमंत्री अपनी रणनीति बदल रहे हैं।

ज्ञान

कसम चुनाव की

चुनाव के तपते महीने के मुहाने पर खड़ा ऋण किसी भी पार्टी के लिए अपवाद नहीं। खुशखबरी यह कि दिसंबर तक की वित्तीय मोहलत में 6200 करोड़ तक का कर्ज उठाने का सामथ्र्य हमें इस लायक बना रहा है कि चुनाव परिणाम कुछ भी रहें, प्रदेश की तकदीर में उधार का भूसा भरा रहेगा। अप्रैल-मई में हजार जमा सात सौ करोड़ की ऋण अनुमति के हम सिकंदर हैं, लेकिन कसम चुनाव की, इसको लेकर कोई बहस नहीं होगी। बहस तो यह होगी कि आखिर कंगना रनौत खाती और पहनती क्या है या आनंद शर्मा कितने अपने-कितने प्रतिशत बाहरी हैं। हमारे मुद्दे टकराऊ हैं जरूर। अगर आप में सामथ्र्य है तो बताएं मेडिकल कालेजों, एम्स तथा पीजीआई सेटेलाइट सेंटर का श्रेय किसे दें। वैसे हम श्रेय लूट कर ही कंगाल हो रहे हैं। घाटे के बस डिपो खोलने का श्रेय, छात्रों के बिना स्कूल-कालेज खोलने का श्रेय और अस्पताल खोलकर डाक्टर की तलाश करने का श्रेय लूटना कोई हिमाचल से सीखे। हमारे चुनाव की सुर्खियां इस काबिल भी नहीं कि पिछले साल के उठाए गए 8300 करोड़ के कर्ज पर अफसोस कर सकें। हमें कौन सी आफत है कि राज्य के मुकद्दर पर बैठे करीब सत्तर हजार करोड़ के ऋण का दुख मनाएं। दुखी तो हम तब होते हैं जब विपक्ष में पहुंचा दिए जाते हैं, वरना सत्ता में रहते हुए तो अदना सा विधायक भी कह उठता है कि प्रदेश में धन की कमी आने नहीं देंगे। वाकई धन है सरकारी नौकरी में और ओल्ड पेंशन स्कीम में। सरकार की हर गारंटी में। हमें मुफ्त में बिजली और महिला होने पर पंद्रह सौ का वजीफा मिल जाए तो दुख काहे का। हमें एचआरटीसी का बढ़ता घाटा नहीं सताता, क्योंकि महिला यात्री बनते ही आधा किराया और करवा चौथ व राखी पर मुफ्त में सरकारी बस पर चढने का मौका मिल जाता है।

जिस प्रदेश की हर साल कर्ज उठाने से नाक नहीं कटती, वहां नागरिक समाज क्यों मुफ्त में खाने से न नुकर करें। हम बीपीएल होकर वीआईपी हो जाते हैं और शुक्रगुजार हैं केंद्र सरकार के कि कुछ हो या न हो, मुफ्त के राशन में हिमाचल का भाषण भी शरीक हो जाता है। हम राज्य और केंद्र की सत्ता में परोसी जा रही रेवडियों के इतने मुरीद हैं कि न प्रदेश और न ही देश की आर्थिकी रास आती है। इस पर तुर्रा यह कि डबल इंजन सरकार बन कर भी हमारी लालटेन में तेल खरीदने की शक्ति नहीं। कहने को हम विद्युत राज्य और शुक्रिया शांता कुमार और नरसिंहा सरकार का कि हिमाचल में पैदा होने वाली बिजली में से मुफ्त की आपूर्ति रायल्टी स्वरूप मिल रही, वरना बीबीएमबी में लटके हमारे वित्तीय अधिकार आज भी सजायाफ्ता हैं। सुक्खू सरकार ने जोश जोश में बीबीएमबी को ललकारा तो केंद्र को पसंद नहीं आया। वाटर सैस लगाकर खजाने को धूप टीका दिया, तो फिर केंद्र को मजा नहीं आया। इधर सुक्खू सरकार आत्मनिर्भरता के लिए शानन विद्युत परियोजना की लीज खत्म होने के बाद, वापसी की प्रतीक्षा कर रही उधर केंद्र व पंजाब के चुनाव हमारे अपने चुनावों को आंखें दिखा रहे हैं। अटल सरकार ने कभी औद्योगिक पैकेज दिया तो बीबीएन ने आर्थिक दवाई बनानी शुरू कर दी, लेकिन इस पैकेज को रोकने वाले अब हिमाचल के हित में वोट मांग रहे हैं।

हिमाचल चुनाव की फेहरिस्त में वेतन-भत्तों की चर्बी एक तरफ और दूसरी तरफ उधार की कड़छी में सारा दारोमदार शीर्षासन कर रहा। चुनाव की डगर में तमाम प्रत्याशियों की वचनबद्धता को सलाम। आम मतदाता को अपने सपने दिखाएं, भले ही चिडियां न जाने कब खेत को चुग चुकी हैं। अब शराब बेचेंगे, तो राज्य की आमदनी बढ़ेगी, वरना रेत-बजरी तो माफिया की नजर में घर कर चुकी है। जिन्हें रोजगार नहीं मिलता चुनाव की दिहाड़ी मिल सकती है।

चुनावी रण में नेतृत्व की परीक्षा

डा. देवेंद्र गुप्ता

कहते है संस्कृति की सत्ता होती है और सत्ता की संस्कृति भी जग जाहिर है। सत्ता की संस्कृति आपको चाटुकारों से घिरा हुआ, अपनों को पुरस्कार, चेयरमैन अध्यक्ष पद से नवाजती है। लेकिन सत्ता की श्रेष्ठता इस बात में है कि वह पार्टी के सक्रिय सदस्यों कार्यकर्ताओं शुभचिंतकों को सत्ता शासन में भागीदार बनाती है और सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को बनाने में सहयोग लेती है'

हिमाचल में आजकल जम कर चुनाव प्रचार हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक है, का आभास देते नजर आ रहे है। यह लेख लिखे जाने के वक्त कांगड़ा और हमीरपुर लोकसभा सीट पर काफी माथापच्ची के बाद क्रमशः आनंद शर्मा और सतपाल रायजादा को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित कर ही दिया है। खैर, यह लेट लतीफी का कांग्रेसी कल्चर है जो खबरों में बना रहता है। सरकार को बने 15 महीने हो गए है। जमीनी हालात यह है कि जनता यह सब सोचने को मजबूर है कि विधान सभा के लिए क्या उपचुनाव राजनीतिक सूझबूझ से टाले नहीं जा सकते थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उपचुनाव के मुद्दे पर जनता को उत्तर देना होगा। सरकार का मुखिया होने के नाते सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी टीम को अपने 15 महीने के शासन के रिकॉर्ड पर जनता के बीच उतरना होगा अपनी सरकार को बचाने व संभाले रखने के लिए यह उपचुनाव जीतना अत्यंत आवश्यक है। भाजपा के विषय में तो यह प्रसिद्ध है कि वह चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है और प्रधानमंत्री मोदी को हर समय चुनावों में सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाले प्रधानमंत्री का तमगा प्राप्त है। प्रधानमंत्री के तौर पर वह कैसे हैं यह लेख का मंतव्य नहीं। उस पर फिर कभी। मुख्यमंत्री सुक्खू के सामने सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकता विधान सभा उपचुनावों की छहों सीटों पर विजयी हासिल करना होगा। लोकसभा के चुनावों में चारों सीटें जीता कर हाई कमान की झोली में डाल कर वह उनके विश्वास को पुख्ता कर सकेंगे।

उन के लिए यह एक अवसर आया है। इस जीत से वह हाई कमान के सामने और प्रदेश कांग्रेस संगठन में विरोधी होली लॉज कैंप के समक्ष नेतृत्व क्षमता साबित करेंगे। जनता का विश्वास और दिल जीतने में सफल हो सकते है। दूसरे, यह जीत इस बात की भी द्योतक होगी कि हाई कमान का सुक्खु को मुख्यमंत्री बनाना और प्रतिभा सिंह की सीएम पद की दावेदारी को नजर अंदाज करने का उनका निर्णय सही था। ऐसे वो कौन से कारण रहे जिनके चलते भली चंगी सरकार पर संकट के बादल मंडराए और उपचुनावों की नौबत झेलनी पड़ गई? याद करें तो एक राजनीतिक घटनाक्रम के चलते प्रदेश की एक मात्र राज्य सभा सीट के लिए चुनाव में भजपा के हाथों मानों छींका ही फूट पड़ा। अल्पमत की भाजपा बहुमत की कांग्रेस की जमीन तले कालीन खिसका कर राज्य सभा सीट का निवाला छीन ले गई। परिणाम यह रहा कि प्रख्यात वकील और कांग्रेस के प्रत्याशी मनु सिंघवी हार गए और कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे और भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन जीत गए। इस प्रकरण से सरकार विशेष कर मुख्यमंत्री के विरुद्ध सुलगते विरोध और आक्रोश से न केवल जनता अवाक रह गई, बल्कि सरकार सुक्खू और उनके चुनावी व संसदीय प्रबंधन को भी इस बात की भनक तक न लगी कि उनके छह विधायक और तीन निर्दलीय वोटिंग के अवसर पर अपनी ही पार्टी के विरुद्ध जाएंगे।

इस प्रकरण ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्य शैली और सरकार चलाने की क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदेश की जनता यह भलीभांति जानती है कि सुक्खू को संगठन का आदमी कहा जाता है और संगठन के वह अच्छे जानकार है। जब तक वीरभद्र मुख्यमंत्री रहे उन्होंने उन्हें दो बार विधायक होने के बावजूद मंत्री या संसदीय सचिव या सरकार में किसी पद से नहीं नवाजा। 1983 में जब वीरभद्र मुख्यमंत्री बने, तब सुक्खू कालेज सी आर के चुनाव लड़ रहे थे। कालेज विश्वविद्यालय की राजनीति करते-करते विभिन्न पदों पर रहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक जा पहुंचे। पंडित सुखराम, विद्यास्टोक्स, आनंद शर्मा, कुलदीप राठौर और शिमला के पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी आदि से सुक्खू की करीबियां जग जाहिर थी। यही बात वीरभद्र को नागवार थीं। अंत समय तक इन दोनों में 36 का आंकड़ा रहा। कहते है संस्कृति की सत्ता होती है और सत्ता की संस्कृति भी जग जाहिर है। सत्ता की संस्कृति आपको चाटुकारों से घिरा हुआ, अपनों को पुरस्कार, चेयरमैन अध्यक्ष पद से नवाजती है। लेकिन सत्ता की श्रेष्ठता इस बात में है कि वह पार्टी के सक्रिय सदस्यों कार्यकर्ताओं शुभचिंतकों को सत्ता शासन में भागीदार बनाती है और सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को बनाने में सहयोग लेती है। अब क्योंकि बारी सुक्खू की आई तो सत्ता का संतुलन बनाने की जगह उन्होंने उन लोगों को पद नवाजे, जो जनता का मत लेकर नहीं आए थे और वीरभद्र गुट की अघोषित अनदेखी कर दी। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर आदि महत्त्वपूर्ण जिलों को मंत्री परिषद में जगह नहीं मिली। प्रदेश के कई वर्ग, जातियां, समूह शासन की हिस्सेदारी से वंचित कर दिए गए। कांगड़ा से सुधीर शर्मा, हमीरपुर से राजेंद्र राणा इस बगावत के सरगना हुए और यह सब भाजपा के खुले समर्थन से हुआ।

जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार को 'मित्रों की सरकार' कह कर संबोधित करते है। यह दीगर है कि वह भी पदों की रेवडियां बांटने में मशगूल रहे। उनका स्वयं का काल विसंगतियों और विरोधाभास का रहा। आजकल विपक्ष में उनकी सक्रियता को देख कर भाजपा के लोग भी यह स्वीकार करते है कि इतनी सक्रियता के साथ उन्होंने भाजपा की सरकर चलाई होती, तो 2022 में कांग्रेस सरकार न बनती। और अब बात करते हैं सुक्खू शासन के व्यवस्था परिवर्तन की बड़ी भूल की, वह है नौकरशाही पर ढीली पकड़। आपने निर्णय लिया कि सरकार बनते ही आप सरकारी बाबूओं को नहीं बदलेंगे। लेकिन वह समय चला गया जब नौकरशाह निर्भीक हो कर राय देते थे। आज समय है कमिटिड ब्योक्रेसी अर्थात समर्पित नौकरशाहों का। आलम यह है कि नौकरशाह भी अब तटस्थ न हो कर भाजपा-कांग्रेस के हो कर रह गए है। ऐसी प्रशासनिक संस्कृति तैयार हो रही है जो स्टील फ्रेम न हो कर रीढ़विहीन हो गई है। चुने हुए विधायकों को इस बात की शिकायत है कि हमारे कार्य नहीं होते, परंतु गैर प्रतिनिधियों, कबिनेट रैंक वाले नेताओं को मुख्यमंत्री और प्रशासन अधिमान देते हैं।

शव संवाद-42

अपने देश में पढ़ाई का दस्तूर कुछ इस तरह है कि जो वर्षों से पढ़े जा रहा है, उसे भी मालूम नहीं आखिर वह पढ़ क्यों रहा है। अब तो पढ़ाने वाले भी तंग आ गए। स्कूल से कालेज और विश्वविद्यालय तक पसरे शिक्षक समाज के लिए जीवन का सबसे कमजोर पक्ष है पढ़ाना। अमूमन अध्यापकों को ही सबसे पहले पता चल रहा है कि अपने देश में शिक्षा ग्रहण करके आदमी कहीं का नहीं रहता, फिर भी यह वर्ग स्वयं में कोशिश करता है कि कम से कम वे तो कहीं के रहें। इसलिए शिक्षा की सबसे बड़ी खोज अध्यापक है। देखते ही पता चल जाता है कि भविष्य में हम क्या कामना कर सकते हैं। खैर देश में साक्षरता दर की खातिर ही सही शिक्षा का अस्तित्व बरकरार है। एक शिक्षा ही है जो चंद बुद्धिजीवियों के अलावा पूरे समाज की अनपढ़ता-अज्ञानता को माइंड नहीं करती। दूसरी ओर बुद्धिजीवी को यह मुगालता है कि एक वही है जो पढ़ाई का प्रोडक्ट है। वह खुद में शिक्षा और शिक्षा में खुद को देखता है। इसलिए सुबह से शाम तक टिप्पणियां करता रहता है। उसे यह भी भ्रम है कि देश को शिक्षा जगत चला रहा है, चला सकता है। उसे भ्रम यह भी है कि देश की अर्थनीति चलाने वालों ने जरूर अर्थशास्त्र पढ़ा होगा या जो एक्सपर्ट बजट की बहस में अर्थशास्त्री के रूप में प्रकट होते हैं, सही कह रहे होते हैं। वैसे सही फैसलों के लिए शिक्षित अधूरे हैं और पूरी है वह शिक्षा जो खोज-खोज कर किसी को सफल नेता बनाती है।

इसीलिए जरूरी नहीं कि शिक्षा मंत्री पूरी तरह शिक्षित हो या चिकित्सा मंत्री के पास संबंधित डिग्री भी हो। वैसे कई मंत्रालय ऐसे भी हैं जहां पढ़ा-लिखा मंत्री फेल हो जाएगा। जिस देश में किसान संघर्ष कर रहे हों, वहां के कृषि मंत्री को पढने की जरूरत है ही कहां? लोग बिन पढ़े भी भारत की जनता को ज्योतिष के जरिए भविष्य बता रहे हैं। दरअसल कई बार तो विशेषज्ञ बनने तक के लिए उचित या संबंधित शिक्षा का कोई ताल्लुक नहीं। देश में ब्लड प्रेशर, गैस्टिक या तरह-तरह की खुजली का निवारण शिक्षा कर ही नहीं पा रही, बल्कि जिन्हें डाक्टरी का ज्ञान नहीं, वे कोई न कोई फार्मूला बता देंगे। फार्मूलों की ईजाद होती ही तब जब हम शिक्षा को गैर जरूरी प्रोडक्ट मानें। वैसे जो पढ़ लिख रहे हैं, वे सभी गैर जरूरी प्रोडक्ट ही तो हैं। बुद्धिजीवी जिस शिक्षा की वजह से बना उसी से डर कर भाग रहा है। उसका माथा अब पढ़ाई झुका रही है। वह न खुद को साबित कर पाया और न ही पढ़ाई को, बल्कि जिसे भी डिग्री में देखता है, भयभीत हो उठता है। अस्पताल में डाक्टर की पढ़ाई से और अदालत में वकील के अध्ययन से सबसे अधिक बुद्धिजीवी ही डरा है। उसने देखा है कि पढ़ाई अब कातिल को बचाने किस शिद्दत से कोर्ट पहुंचती है और दिल वालों को दिल का मरीज किस तरह अस्पतालों में पहुंच कर बनाती है।

बुद्धिजीवी इलेक्टोरल बांड से नहीं डरा, लेकिन डर गया उस सियासत से जो छोटे से चुनाव में भी करोड़ों खर्च करने का जोखिम उठाती है। अंततः फेसबुक और व्हाट्सऐप तक पहुंची पढ़ाई से इतना डर गया बुद्धिजीवी कि मुंह छिपाता भाग रहा है। उसे भागते देख शिक्षा की सारी व्यवस्था खुश है। बिना छात्रों के स्कूल और स्कूलों के अध्यापक खुश हैं। बुद्धिजीवी भागते हुए एक फ्लाईओवर के नीचे पल भर के लिए रुका, तो सामने पोस्टर डराने लगे, 'दसवीं फेल सीधे पास करें बीए।' वहां रद्दी के ढेरों के बीच वार्षिक परीक्षाओं की आंसर शीट से कुछ बच्चे लिफाफे बना रहे थे। उन्हें मालूम था कि हजारों उत्तर पुस्तिकाओं से बने लिफाफे से उनकी दिहाड़ी बनाएंगे। बुद्धिजीवी अंदाजा लगाने लगा कि एक बुद्धिजीवी उम्र भर पढ़ाई के लिए कितने भी कागज लिख ले, उनकी कीमत में लिफाफे सिर्फ चंद पैसों में ही बिकेंगे। रद्दी के भीतर छुपी पढ़ाई लगभग मर चुकी थी। बुद्धिजीवी ने उसे फिर से पढने की कोशिश की, 'देश में इस साल भी वार्षिक परीक्षाओं में असफल हजारों छात्रों ने खुदकुशी की।' तब तक बुद्धिजीवी की हालत देखकर बची खुची पढ़ाई शव में बदल चुकी थी। सच में हर लिफाफे पर पढ़ाई के न जाने कितने शव ढोते हैं, रेहड़ी-फड़ी पर धंधा करने वाले। -क्रमशः

लेनदेन के ब्योरे को हटाकर ई-रुपया को बनाया जा सकता है गोपनीय- शक्तिकांत दास

परिवहन विशेष न्यूज

BIS इनोवेशन समिट में बोलते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में मदद के लिए प्रोग्रामेबिलिटी फीचर पेश करने के साथ-साथ सीबीडीसी को ऑफलाइन मोड में हस्तांतरणीय बनाने पर भी काम कर रहा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2022 के अंत में सीबीडीसी की शुरुआत के बाद से गोपनीयता पहलू के बारे में चिंताएं रही हैं।

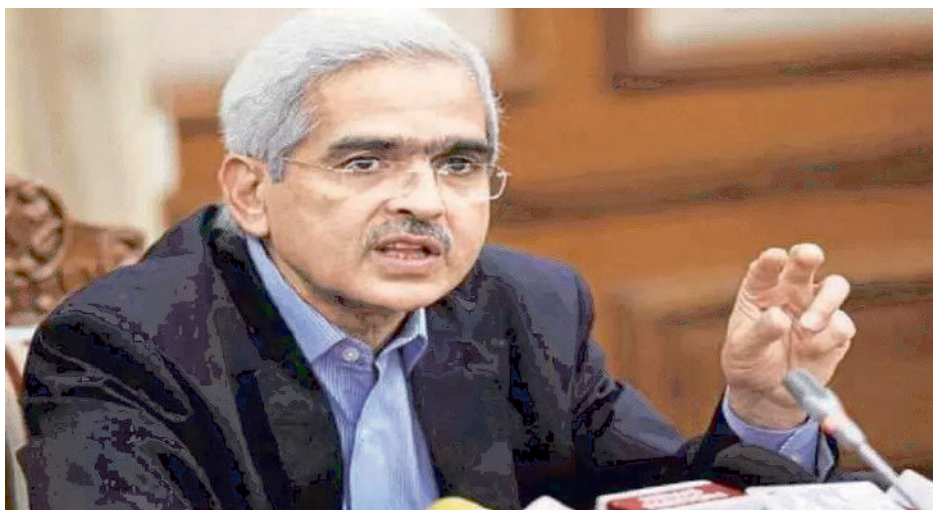

नई दिल्ली। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि लेनदेन के ब्योरे को स्थायी रूप से हटाकर ई-रुपये या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को गोपनीय बनाया जा सकता है। इससे यह कागजी मुद्रा के समान हो जाएगी। बीआईएस इनोवेशन सम्मेलन में दास ने कहा कि सीबीडीएस के ऑफलाइन हस्तांतरण को लेकर भी काम किया जा रहा है।

2022 के अंत में सीबीडीसी की लॉन्चिंग के साथ इसकी गोपनीयता को लेकर चिंता बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि सीबीडीसी से लेनदेन का रिकार्ड तैयार हो जाता है, जबकि कागजी मुद्रा के लेनदेन में गोपनीयता बनी रहती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कानून या टेक्नोलाजी से ई-रुपये की गोपनीयता से जुड़ी चिंता दूर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अभी भी खुदरा लेनदेन में यूपीआई को प्राथमिकता दी जा रही है लेकिन आने वाले समय में यह स्थिति बदल सकती है।

बीआईएस इनोवेशन समिट में बोलते हुए दास ने कहा कि भारत अपने वित्तीय समावेशन लक्ष्यों में मदद के लिए प्रोग्रामेबिलिटी फीचर पेश करने के साथ-साथ सीबीडीसी को ऑफलाइन मोड में हस्तांतरणीय बनाने पर भी काम कर रहा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2022 के अंत में सीबीडीसी की शुरुआत के बाद से गोपनीयता पहलू के बारे में चिंताएं रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति एक निशान छोड़ देगी जहां सभी मुद्रा का उपयोग किया गया है, नकदी के विपरीत जो गुमनामी प्रदान करती है।

उन्होंने कहा कि मूल सिद्धांत यह है कि सीबीडीसी में नकदी के समान ही गुमनामी की डिग्री हो सकती है, न अधिक और न कम। अतीत में दास और उनके डिप्टी टी रबी शंकर सहित आरबीआई अधिकारियों ने कहा है कि प्रौद्योगिकी गोपनीयता पर ऐसी चिंताओं का समाधान प्रदान करती है।

इस बीच दास ने दोहराया कि भारत सीबीडीसी को ऑफलाइन मोड में भी हस्तांतरणीय बनाने पर काम कर रहा है, उन्होंने बताया कि नकदी की प्रमुख विशेषताओं में से एक यह है कि इसे काम करने के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं है। इस साल फरवरी में दास ने सीबीडीसी की ऑफलाइन और प्रोग्राम योग्यता सुविधाओं की घोषणा की।

छह वर्षों के उच्च स्तर पर पी-नोट्स के जरिये निवेश, फरवरी के अंत तक पार हुआ 1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा

मार्केट रेगुलेटर सेबी के ताजा डाटा के अनुसार फरवरी के अंत में इक्विटी डेट और हाइब्रिड सिक्युरिटीज में पी-नोट्स के जरिये निवेश 149517 करोड़ रुपये रहा है जो जनवरी के अंत में 143011 करोड़ रुपये था। जून 2017 के बाद यह निवेश उच्च स्तर पर पहुंचा है। डाटा के अनुसार तब पी-नोट्स के जरिये 1.65 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ था।

नई दिल्ली। देश के पूंजी बाजारों में पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के जरिये निवेश फरवरी के अंत तक बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है जो बीते छह वर्षों का उच्च स्तर है। घरेलू आर्थिकी के मजबूत प्रदर्शन से पूंजी बाजारों में पी-नोट्स के जरिये निवेश बढ़ रहा है।

पी-नोट्स विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की ओर से ऐसे विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो भारतीय शेयर बाजारों में बिना पंजीकरण निवेश करना चाहते हैं।

मार्केट रेगुलेटर सेबी के ताजा डाटा के अनुसार, फरवरी के अंत में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड सिक्युरिटीज में पी-नोट्स के जरिये निवेश 1,49,517 करोड़ रुपये रहा है जो जनवरी के अंत में 1,43,011 करोड़ रुपये था। जून 2017 के बाद यह निवेश उच्च स्तर पर पहुंचा है। डाटा के अनुसार, तब पी-नोट्स के जरिये 1.65 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ था।

डाटा के अनुसार, 1.5 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश में से इक्विटी में 1.27 लाख करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। वहीं, डेट बाजारों में 21,303 करोड़ रुपये और हाइब्रिड सिक्युरिटीज में 541 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। फरवरी के अंत में भारतीय बाजारों में एफपीआइ के अधीन परिसंपत्तियों का मूल्य 68.55 लाख करोड़ रुपये था, जो इससे पिछले महीने में 66.96 लाख करोड़ रुपये था।

भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तावित नियमों का खौफ, धड़ाम हुए पीएनबी, बीओबी, केनरा बैंक और यूनियन बैंक के शेयर

परिवहन विशेष न्यूज

देश के बैंकिंग सेक्टर का वित्तीय प्रदर्शन पिछले दो वर्षों से शानदार आ रहा है। कमाई बढ़ रही है और मुनाफा भी बढ़ रहा है। सोमवार को दो सरकारी बैंकों के वित्तीय परिणाम (जनवरी से मार्च 2024 की तिमाही) आए हैं जो काफी अच्छे रहे हैं। इसके बावजूद 06 मई 2024 को शेयर बाजार में तकरीबन सभी बैंकों के शेयरों के भाव धड़ाम हो गये। आइए जानते हैं इसकी वजह।

नई दिल्ली। देश के बैंकिंग सेक्टर का वित्तीय प्रदर्शन पिछले दो वर्षों से शानदार आ रहा है। कमाई बढ़ रही है और मुनाफा भी बढ़ रहा है। सोमवार को दो सरकारी बैंकों के वित्तीय परिणाम (जनवरी से मार्च, 2024 की तिमाही) आए हैं, जो काफी अच्छे रहे हैं। इसके बावजूद 06 मई, 2024 को शेयर बाजार में तकरीबन सभी बैंकों के शेयरों के भाव धड़ाम हो गये।

क्या रही शेयरों में गिरावट की वजह

बैंकिंग शेयरों में गिरावट का कारण पिछले हफ्ते आरबीआई की तरफ से सभी तरह के बैंकों व गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लाए गए नए नियम के प्रस्ताव को बताया जा रहा है। इसके मुताबिक परियोजनाओं को कर्ज मुहैया कराने वाले सभी बैंकों (एनबीएफसी, सहकारी बैंक आदि समेत) को अब अपने मुनाफे का पांच फीसद अतिरिक्त राशि अलग से संयोजित करनी पड़ सकती है।

इसका असर यह रहा कि बाजार में पीएनबी के शेयर भाव में 6.41 फीसद, केनरा बैंक में 5.42 फीसद, बैंक ऑफ बड़ौदा में 3.71 फीसद, यूनियन बैंक में 3.12 फीसद की गिरावट आई है।

मुनाफे पर नहीं होगा कोई असर!

आरबीआई के प्रस्तावित नियम का भय इतना ज्यादा है कि बाजार खुलने से पहले कई निवेश सलाहकार एजेंसियों ने यह रिपोर्ट जारी कि इससे बैंकों के मुनाफे पर कोई असर नहीं होगा। अगर कुछ असर होगा भी तो वह पावर फाइनेंस कार्पोरेशन और आरईसी जैसी कंपनियों पर होगा, जो काफी ज्यादा परियोजनाओं को लोन मुहैया कराती हैं। सोमवार को पीएफसी के शेयर भाव में 8.93 फीसद और आरईसी के शेयर भाव में 7.35 फीसद की गिरावट दर्ज की गई है।

जानकारों का कहना है कि आरबीआई ने नया नियम बड़ी संख्या में ढांचागत परियोजनाओं को कर्ज देने की स्थिति के सामने आने की वजह से लागू करने की तैयारी की है। अगर बाद में इन परियोजनाओं से कर्ज वसूलने में दिक्कत आएगी तो समायोजित राशि से बैंक अपनी स्थिति सुरक्षित रख सकता है। इससे बैंक भविष्य में फंसे कर्ज (एनपीए) की समस्या से भी बच सकेंगे।

भारतीय कंपनियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात में होगी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी, Crisil ने बताया कैसे हासिल होगा लक्ष्य

क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अंतरराष्ट्रीय यातायात में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के चलते भारतीय एयरलाइन कंपनियों की व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी जो घरेलू क्षेत्र की तुलना में अधिक लाभदायक है। क्रिसिल के अनुसार भारत का अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात वित्त वर्ष 2023-24 में करीब सात करोड़ तक बढ़ गया। यह वैश्विक महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया है।

मुंबई। भारतीय विमानन कंपनियां (Indian Airlines) वित्त वर्ष 2027-28 तक देश के अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात (International Traffic) की 50 प्रतिशत जरूरत को पूरा करने में सक्षम होंगी। पिछले वित्त वर्ष में यह हिस्सेदारी 43 प्रतिशत थी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (Crisil) के अनुसार, "यह सुधार भारतीय कंपनियों द्वारा अतिरिक्त विमानों की तैनाती और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नए मार्ग जोड़ने के साथ-साथ विदेशी एयरलाइन की तुलना में बेहतर घरेलू संपर्क के बल पर होगा।"

क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अंतरराष्ट्रीय यातायात में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी के चलते भारतीय एयरलाइन कंपनियों की व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी, जो घरेलू क्षेत्र की तुलना में अधिक लाभदायक है। क्रिसिल के अनुसार, भारत का अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात वित्त वर्ष 2023-24 में करीब सात करोड़ तक बढ़ गया। यह वैश्विक महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया है। वैश्विक महामारी से प्रभावित वित्त वर्ष 2020-21 में यह एक करोड़ के निचले स्तर पर आ गया था।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक मनीष गुप्ता ने कहा, "बढ़ती खर्च योग्य आय, आसान वीजा पहुंच, हवाई अड्डों की बढ़ती संख्या और बेहतर हवाई यात्रा संपर्क से अंतरराष्ट्रीय यात्रा को बढ़ावा मिल रहा है।" रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय एयरलाइन ने पिछले 15 महीनों में 55 नए अंतरराष्ट्रीय मार्ग जोड़े हैं, जिससे उनकी संख्या 300 से अधिक हो गई है। इनमें अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लंबी दूरी के गंतव्यों के लिए सीधी उड़ान शामिल हैं।

ISMA ने रखी सरकार से 20 लाख टन चीनी निर्यात की डिमांड, किसानों को मिलेगा लाभ

कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलों से 5-6 लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन की उम्मीद है। इस तरह शुद्ध चीनी उत्पादन 320 लाख टन के करीब होने का अनुमान है। पिछले विपणन वर्ष में चीनी मिलों को लगभग 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। ISMA ने सोमवार को बयान में कहा कि अप्रैल 2024 के अंत तक उत्पादन लगभग 314 लाख टन तक पहुंच गया है।

नई दिल्ली। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने सरकार से सितंबर में खत्म होने वाले चालू मार्केटिंग सीजन में 20 लाख टन चीनी निर्यात की अनुमति देने का आग्रह किया है। मिल मालिकों का मानना है कि सरप्लस चीनी के निर्यात से उनके पास नकदी आएगी, जिससे वे किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान कर सकने में सक्षम होंगे।

20 लाख टन चीनी निर्यात की डिमांड

मौजूदा 2023-24 विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के लिए सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए चीनी निर्यात की अनुमति नहीं दी है। पिछले मार्केटिंग सीजन में चीनी मिलों को लगभग 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आइएसएमए) ने सोमवार को कहा कि अप्रैल, 2024 के अंत तक चीनी का उत्पादन लगभग 314 लाख टन तक पहुंच गया है।

शुद्ध चीनी उत्पादन 320 लाख टन होने का अनुमान

कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलों से 5-6 लाख टन के अतिरिक्त उत्पादन की उम्मीद है और इस तरह शुद्ध चीनी उत्पादन 320 लाख टन के करीब होने का अनुमान है। पिछले विपणन वर्ष में चीनी मिलों को लगभग 60 लाख टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई थी। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (ISMA) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि अप्रैल 2024 के अंत तक उत्पादन लगभग 314 लाख टन तक पहुंच गया है।

1 अक्टूबर 2023 तक लगभग 56 लाख टन के शुरुआती स्टॉक और सीजन के लिए 285 लाख टन की अनुमानित घरेलू खपत को ध्यान में रखते हुए ISMA ने 30 सितंबर 2024 तक 91 लाख टन के काफी अधिक समापन स्टॉक का अनुमान लगाया है। एसोसिएशन को कई कारकों के कारण 2024-25 में मध्यम पेराई सत्र की भी उम्मीद है, जिसमें गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में वृद्धि की शीघ्र घोषणा, अनुकूल प्री-मानसून वर्षा और सामान्य से अधिक मानसून का संकेत देने वाले पूर्वानुमान शामिल हैं। इन कारकों से आने वाले वर्ष में और अधिक स्टॉक बढ़ने की उम्मीद है।

जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष को सीतारमण ने दिलाई शपथ

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संजय कुमार मिश्रा (Sanjaya Kumar Mishra) को सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मिश्रा की नियुक्ति जीएसटीएटी के संचालन की शुरुआत का प्रतीक है, जो जीएसटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण निकाय है।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं

जीएसटीएटी के पहले अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति मिश्रा झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इस मौके पर सीतारमण ने कहा कि जीएसटी से जुड़ी दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई। एक उपलब्धि जीएसटीएटी के अध्यक्ष की नियुक्ति है तो दूसरी उपलब्धि अप्रैल में जीएसटी संग्रह का दो लाख करोड़ के पार जाना है। उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली के लागू होने से अप्रत्यक्ष करों को एक लय में लाया गया।

जीएसटी प्रणाली में गरीबों का अधिक ध्यान रखा गया और इससे वित्तीय संघीय ढांचे को प्रोत्साहन मिला। जीएसटीएटी केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत स्थापित एक अपीलीय प्राधिकरण है, जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उक्त अधिनियम और संबंधित राज्य-केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियमों के तहत विभिन्न अपीलों की सुनवाई करता है।

असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा का इंतजाम करेगी सरकार, बड़ी कंपनियों को देना होगा वित्तीय योगदान

असंगठित सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के साथ सभी प्रकार के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार फंड की स्थापना करेगी। गिग वर्कर्स से काम लेने वाली कंपनियों को अपनी कमाई का एक से दो प्रतिशत तक का योगदान देना पड़ सकता है। सरकार के श्रम कानून की अवहेलना करने वाली कंपनियों से लिया जाने वाला जुर्माना भी सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा होगा।

नई दिल्ली। असंगठित सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के साथ सभी प्रकार के गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार फंड की स्थापना करेगी। गिग वर्कर्स से काम लेने वाली कंपनियों को अपनी कमाई का एक से दो प्रतिशत तक का योगदान देना पड़ सकता है। सरकार जो श्रम कानून ला रही है, उसकी अवहेलना करने वाली कंपनियों से जुर्माने में ली जाने वाली राशि भी सामाजिक सुरक्षा फंड में जमा होगी।

सभी गिग वर्कर्स का पंजीयन अनिवार्य होगा और उनके पंजीयन की जिम्मेदारी भी इनसे काम लेने वाली कंपनियों की हो सकती है। केंद्र सरकार असंगठित सेक्टर एवं सभी गिग वर्कर्स को इलाज से लेकर भविष्य निधि जैसी सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन कर सकती है। अस्पताल में इलाज की सुविधा गिग वर्कर्स के साथ उनके परिवार को भी दी जाएगी।

क्या है सरकार की योजना ?

इस काम को अंजाम देने के लिए पिछले कुछ दिनों से श्रम व रोजगार मंत्रालय में लगातार मंथन चल रहा है और जल्द ही इस नियम को अंतिम रूप दिया जा सकता है जिस पर नई सरकार अपनी मुहर लगाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार लागू के लिए तैयार श्रम संहिता के चार पार्ट के महत्वपूर्ण नियमों को मिलाकर एक नई संहिता ला रही है और गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा इस नई संहिता का हिस्सा है। निर्माण से जुड़ी कंपनियों से सामाजिक सुरक्षा कोष के लिए सेस वसूले जा सकते हैं।

गिग वर्कर्स मुख्य रूप से विभिन्न सेक्टर में उनकी मांग के मुताबिक दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों को कहा जाता है। वैसे ही, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एप जैसे कि जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर के लिए काम करने वाले प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी पूरी सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी।

घरेलू सहायकों को भी सामाजिक सुरक्षा

सरकार घरों में काम करने वाले सहायक या सहायिका की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी योजना बना रही है। इसके तहत सरकार घरों के मालिक से इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए आर्थिक योगदान की अपील कर सकती है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई खाना पकाने वाला आता है और वह अटल पेंशन योजना से जुड़ा है तो आप उसकी किस्त भर सकते हैं।

मंत्रालय का मानना है कि लोग अपने घरों में काम करने वालों को दिवाली, होली या कई अन्य मौके पर उपहार या राशि देते हैं। इसकी जगह वह इनकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी वित्तीय जिम्मेदारी ले सकते हैं। काम छोड़ देने पर यह जिम्मेदार उस घर मालिक की हो जाएगी जिनके यहां वह काम शुरू करेगा।

उडीशा मे बीजेपी सरकार बनाएगी, 10 जून को बीजेपी मुख्यमंत्री शपथ लेगा : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

भुबनेश्वर : चुनाव नतीजे 4 जून को जारी होंगे। इससे काफी पहले ही प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि ओडिशा में बीजेपी सरकार बनाएगी। मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी का मुख्यमंत्री 10 जून को ओडिशा में शपथ लेगा। इसके अलावा मोदी ने कहा कि 4 जून बीजू जनता दल सरकार की समाप्ति तिथि है। ब्रह्मपुर में मोदी शुरू से ही बीजेडी पर निशान लगाएं। उन्होंने सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 4 जून ओडिशा में बीजे सरकार की समाप्ति तिथि है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे की घोषणा 6 जून को की जाएगी। 10 जून को बीजेपी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। इसलिए मैं सभी को शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। ओडिशा में बिजेड़ी का पतन हो रहा है, कांग्रेस लुप्त हो रही है, लोगों को बीजेपी पर भरोसा है। बीजेपी के लिए उम्मीद की एक नई किरण उभरी है। ओडिशा में प्रचुर मात्रा में पानी, खनिज संसाधन, लंबा समुद्री तट, ब्रह्मपुर जैसा व्यापार केंद्र है। भगवान ने ओडिशा को बहुत कुछ दिया है। लेकिन यह पूछने पर कि इतनी संपत्ति वाले ओडिशा के लोग गरीब क्यों हैं, मोदी ने कहा कि ओडिशा अमीर है, लेकिन लोग गरीब हैं।

वहीं, मोदी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में ओडिशा को 3.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए हैं। खाली पैसा भेजने से काम नहीं चलेगा, पैसा खर्च करने के लिए अच्छी सरकार चाहिए। दिल्ली से पैसा आ रहा है, योजना बन रही है लेकिन बिजेड़ी सरकार इसे यहां लागू न करे, नहीं तो केंद्र की योजना पर अड़ी रहेगी और अपना दावा करेगी। मोदी सरकार मुफ्त चावल के लिए पैसे भेज रही है, लेकिन यहां बिजेड़ी सरकार स्टिकर लगाकर प्रचार कर रही है कि वह चावल खुद दे रही है। मोदी ने कहा कि वह कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ किया होता तो केंद्रीय योजना पर स्टीकर क्यों लगाते?

इसरो विकसित कर रहा तरल ऑक्सीजन केरोसिन चालित सेमी-क्रायोजेनिक इंजन, पहला इग्निशन परीक्षण सफल

सेमी-क्रायो प्री-बर्नर का सफल इग्निशन परीक्षण सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली के विकास में बड़ी उपलब्धि है। इसरो के अनुसार सेमी-क्रायोजेनिक इंजन इग्निशन स्टार्ट फ्यूल एम्प्यूल का उपयोग करके किया गया। इसमें ट्राइथाइल एल्युमनाइड और ट्राइथाइल बोरान के संयोजन का उपयोग किया गया। इसरो में 2000 किलोन्यूटन सेमी-क्रायोजेनिक में पहली बार इसका उपयोग किया है। लिक्विड रॉकेट इंजन सिस्टम के विकास में इग्निशन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

बेंगलुरु। इसरो सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। इसका मकसद प्रक्षेपण यान मार्क-3 (एलवीएम3) की पेलोड क्षमता बढ़ाना है। यह तरल ऑक्सीजन (एलओएक्स) केरोसीन प्रणोदक संयोजन पर काम करने वाला 2,000 किलोन्यूटन थ्रस्ट का इंजन होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने सोमवार को कहा इंजन के विकास के तहत सेमी- क्रायो प्री बर्नर का पहला इग्निशन परीक्षण दो मई को इसरो प्रणोदन परिसर महेंद्रगिरि में सेमी क्रायो एकीकृत इंजन परीक्षण केंद्र (एसआईईटी) में सफलतापूर्वक किया गया।

सेमी-क्रायो प्री-बर्नर का सफल इग्निशन परीक्षण सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली के विकास में बड़ी उपलब्धि है। इसरो के अनुसार, सेमी-क्रायोजेनिक इंजन इग्निशन स्टार्ट फ्यूल एम्प्यूल का उपयोग करके किया गया। इसमें ट्राइथाइल एल्युमनाइड और ट्राइथाइल बोरान के संयोजन का उपयोग किया गया।

इसरो में 2000 किलोन्यूटन सेमी-क्रायोजेनिक में पहली बार इसका उपयोग किया है। लिक्विड रॉकेट इंजन सिस्टम के विकास में इग्निशन प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इसके बाद इंजन पावरहेड टेस्ट आर्टिकल और पूरी तरह से एकीकृत इंजन के परीक्षण किए जाएंगे।

इनर व्हील क्लब के सहयोग से नेत्र रोगियो को मिलेगी नेत्र ज्योति

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। इनर व्हील क्लब भीलवाड़ा एवं बूंदी के सहयोग से, श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति एवं अन्धता निवारण सोसाइटी के तत्वाधान चार दिवसीय निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर में 37 नेत्र रोगियों के आंखों की जांच की गई। इस बार के नेत्र शिविर में इनर व्हील क्लब बूंदी अध्यक्ष सुनीता सोमानी, सचिव निशा गुप्ता एवं इनर व्हील क्लब भीलवाड़ा अध्यक्ष रीता गोयल, सचिव सुमित्रा वैष्णव का विशेष सहयोग रहा इस अवसर पर समिति अध्यक्ष उदयलाल समदानी, जे के मित्तल, रामनारायण सोमानी, गणपत जागेटीया, सुभाष गर्ग, अरुण जागेटिया, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, दयाशंकर शुक्ला, श्यामसुंदर पारीक, सुरेश नथरानी, राघव गगरानी शांता सोमानी ने सेवाएं दी। मीडीया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि 7मई को डॉ कृष्णा हेडा वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा स्पर्श हॉस्पिटल, टंकी के बालाजी के सामने चयनित रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किए जाएंगे।

जाने क़ाराक़ोरम दर्रा के बारे में

क़ाराक़ोरम दर्रा काराकोरम पर्वतमाला में भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य और जनवादी गणतंत्र चीन द्वारा नियंत्रित शिंजियांग प्रदेश के बीच 4693मीटर (15396 फ़ुट) की ऊँचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह लद्दाख़ के लेह शहर और तारिम द्रोणी के यारकन्द क्षेत्र के बीच के प्राचीन व्यापिरिक मार्ग का सबसे ऊँचा स्थान है। यह दर्रा अत्यंत ऊँचाई पर है और दूर-दूर तक कोई वनस्पति नहीं उगता जिस से यहाँ से गुज़रते कारवानों में बहुत से जानवर दम तोड़ देते थे। इस कारण राह पर जानवरों की हड्डियाँ बिखरी रहती थीं। लेह जाते हुए इस दर्रे से दक्षिण में लगभग 5300 मीटर (17400 फ़ुट) की ऊँचाई पर देपसंग मैदान है।

कराकोरम दर्रे पर एक संभावित चीन-भारत-पाकिस्तान त्रिबिन्दु को 1963 में चीन और पाकिस्तान के बीच ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट के संबंध में संदर्भित किया गया है, लेकिन भारत उस संधि के पक्ष में नहीं था और न ही किसी त्रिबिन्दु समझौते पर।

संपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर, सॉल्टोरो रिज (सिया ला, बिलाफोंड ला, ग्योंग ला, याराम ला (6,100 मी), और चुलुंग ला (5,800 मी।

न्यायिक अधिकारियों की भर्ती में समयसीमा का पालन नहीं करने से SC खफा, 25 में से सिर्फ 9 राज्यों ने पूरी की नियुक्ति प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात की निंदा की कि न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद 25 राज्यों में से केवल नौ राज्यों ने निर्धारित समय के भीतर सिविल जजों की नियुक्ति पूरी की। जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में समयसीमा का पालन होना चाहिए।

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात की निंदा की कि न्यायिक अधिकारियों की भर्ती के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद 25 राज्यों में से केवल नौ राज्यों ने निर्धारित समय के भीतर सिविल जजों की नियुक्ति पूरी की।

शीर्ष अदालत ने जिला और अधीनस्थ अदालतों में रिक्तियों को भरने के लिए एक समय सीमा का पालन करना अनिवार्य किया था। यह प्रक्रिया 31 मार्च को शुरू होनी थी और उसी वर्ष 31 अक्टूबर तक समाप्त होनी थी। लेकिन कई हाई कोर्टों के अनुरोध पर कार्यक्रम को संशोधित किया गया था।

पीठ ने क्या कहा?

जस्टिस हृषिकेश राय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में समयसीमा का पालन होना चाहिए, लेकिन यदि कोई विशेष और अपरिहार्य आवश्यकता है, तो हितधारकों को उचित तत्परता के साथ सूचित किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने उस फैसले में ये टिप्पणियां कीं, जिसके जरिये उसने बिहार और गुजरात में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के हिस्से के रूप में मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने वाले नियमों को बरकरार रखा।

नौ राज्यों ने पूरी की निर्धारित समय के भीतर सिविल जजों की नियुक्ति

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मलिक मजहर (सुप्रा) के फैसले में भर्ती के लिए समयसीमा निर्धारित करने के बावजूद 25 में से केवल नौ राज्यों ने सिविल जज (जज डिवीजन) की भर्ती निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार को विज्ञापन की तिथि (9 मार्च, 2020) से अंतिम परिणाम की तिथि (10 अक्टूबर, 2022) तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में 945 दिन लगे। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में न्यायिक सेवा परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक समय-सारिणी के महत्व पर जोर दिया था।

पीठ ने तथ्यों का दिया हवाला

मौजूदा मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि बिहार चयन प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जनवरी, 2015 में जारी किया गया था; अंतिम उम्मीदवार को अगस्त, 2016 में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इसी तरह, गुजरात में सिविल जजों के चयन के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था, लेकिन चयन प्रक्रिया 2021 में पूरी हो सकी। न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के तहत मौखिक परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित करने वाले नियमों को बरकरार रखते हुए शीर्ष अदालत ने न्यायिक सेवाओं, अभ्यर्थियों और जिला न्यायपालिका में जजों के लिए धीमी चयन प्रक्रिया की चिंताओं को ध्यान में रखा। इस क्रम में शीर्ष अदालत ने कई निर्देश भी जारी किए जिसमें यह निर्देश भी शामिल है कि हाई कोर्टों को अभ्यर्थियों के मुद्दों से निपटने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं, कार्यों एवं दायित्वों के साथ एक नामित प्राधिकारी को अधिसूचित करना चाहिए।

पीठ ने बिहार और गुजरात की जिला न्यायिक सेवाओं के विभिन्न असफल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचिकाओं में यह सवाल उठाया गया था कि क्या साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करना सुप्रीम कोर्ट के ऑल इंडिया जजेस केस के 2002 के फैसले का उल्लंघन है। फैसले में कहा गया कि साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित करना स्वीकार्य है और यह ऑल इंडिया जजेस केस (2002) का उल्लंघन नहीं है।

लोकसभा चुनाव में डीपफेक और AI को लेकर चुनाव आयोग सख्त, सोशल मीडिया से 3 घंटे में हटाने होंगे फर्जी पोस्ट

चुनाव आयोग ने यह दिशा-निर्देश सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनाव प्रचार के दौरान जिम्मेदारी और शुचिता का पालन करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस नेता राहुल गांधी बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और अभिनेता रणवीर सिंह के डीपफेक वीडियो को कुछेक सोशल मीडिया हैंडल से हटाया गया है।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर फर्जी विषय सामग्रियों को लेकर राजनीतिक दलों को कड़ी हिदायत दी है। आयोग ने सभी दलों से कहा कि उनके संज्ञान में लाई गई फर्जी पोस्टों को शिकायत के तीन घंटे के अंदर ही सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटाना होगा। चुनाव आयोग ने यह दिशा-निर्देश सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनाव प्रचार के दौरान जिम्मेदारी और शुचिता का पालन करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान और अभिनेता रणवीर सिंह के डीपफेक वीडियो को कुछेक सोशल मीडिया हैंडल से हटाया गया है। इन आपराधिक मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। चुनाव आयोग ने पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स की मदद से डीपफेक कंटेंट नहीं बनाएं और ना ही किसी जानकारी को तोड़-मरोड़ कर पेश करें। दुष्प्रचार और गलत जानकारी शेयर करने से बचें, ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुचिता कायम रहे।

कांग्रेस ने की केंद्र सरकार की चीन नीति की आलोचना, चीनी घुसपैठ को लेकर साधा निशाना

परिवहन विशेष न्यूज

कांग्रेस ने चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि क्या सरकार ने देपसांग और डेमचोक में हजारों वर्ग किलोमीटर चीन को आत्मसमर्पित कर दिया है या क्या वह अब भी पांच मई 2020 से पहले की स्थिति पर लौटने की कोशिश कर रही है। रमेश ने यह भी कहा कि चार वर्षों में 21 दौर की सैन्य वार्ता के बावजूद स्थिति प्रतिकूल बनी हुई है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि क्या सरकार ने देपसांग और डेमचोक में हजारों वर्ग किलोमीटर चीन को 'आत्मसमर्पित' कर दिया है या क्या वह अब भी पांच मई 2020 से पहले की स्थिति पर लौटने की कोशिश कर रही है।

जयराम रमेश ने क्या कहा?

पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग त्सो में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प की चौथी बरसी पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि क्या किसी को कई दशकों में भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक और खुफिया चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए पूछा कि क्या आप अब भी अपने 19 जून 2020 के बयान पर विश्वास करते हैं, जो गलवान में हमारे 20 सैनिकों के शहीद होने के बाद दिया गया था। ना कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है।

अभी भी प्रतिकूल बनी हुई है स्थितिः रमेश

रमेश ने यह भी कहा कि चार वर्षों में 21 दौर की सैन्य वार्ता के बावजूद स्थिति प्रतिकूल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि लेह के पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट रूप से दिखाया है कि हमारे सैनिक 65 गश्त बिंदुओं में से 26 तक पहुंचने में असमर्थ थे, जहां वे पांच मई 2020 से पहले पहुंच सकते थे।

भारतीय लोकतंत्र

आज का सच, राजनीतिक सफर में सीधा पहुंचने का सरल रास्ता आप भी पढ़ कर मान जाएंगे सही है सच जो किसी के द्वारा बताया गया और हम को लगा आपकों भी बता दें।

जज : क्या तुमने नारा लगाया था कि भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे'?

आरोपित : जी हां'!!

जज : क्या तुमने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था'?

आरोपी : जी हां'!!

जज : क्या आप ने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध और अपमान किया'?

आरोपित : जी हां'!!

जज : क्या आप ने आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन किया'?

आरोपित : जी हां'!!

जज : क्या आप ने सेना, पुलिस के खिलाफ हथियार उठाने का समर्थन किया था'?

आरोपित : जी हां'!!

जज : क्या आप ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया'?

आरोपित : जी हां'!!

जज : क्या तुमने भारत में पाकिस्तान का झंडा फहराया'?

आरोपित : जी हां जज साहब, मैंने ये सब किया है।

जज : तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम इस देश के नागरिक नहीं हो, जानते हो इस देशद्रोह की सजा क्या है'?

आरोपी : जी हाँ जज साहब, मैं इन सबसे परिचित हूँ और यह मैंने बहुत सोच समझकर किया है। इससे पहले मैं एक गुमनाम व्यक्ति था, छोटी-छोटी चीजों के लिए तरसता था, लेकिन जब से मैंने ऐसा किया है तब से मैं सम्माननीय लोगों की श्रेणी में आ गया हूँ।

राहुल, सोनिया, लालू पुत्र, माया, अखिलेश, ममता, पवार, देवेगौड़ा, येचुरी, अब्दुल्ला, केजरीवाल₹ जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बड़े-बड़े नेता आज मुझसे मिलने के लिए बेचैन हैं। मेरे पास दिन भर फोन आ रहे हैं, कोई न कोई रोज सुबह-शाम मुझसे मिलने आता है। अच्छे-अच्छे राजनीतिक विश्लेषक मेरी विचारधारा पर बहस कर रहे हैं। रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, प्रसून जोशी और शेखर गुप्ता जैसे पत्रकार मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया में मुझ पर लेख लिखे जा रहे हैं, टीवी चैनलों पर मुझ पर बहस हो रही है।

आरोपी : जज साहब, कल मुझे छोटी सी नौकरी की चिंता थी लेकिन आज बड़ी-बड़ी पार्टियों से विधानसभा और संसदीय चुनाव लड़ने के प्रस्ताव आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ से, लेकिन करोड़ों रुपये मेरे खाते में आ गये।

जज : लेकिन ये देशद्रोह है, आप पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है।

आरोपित कोई बात नहीं। कपिल सिब्बल, मनु सांघवी, प्रशांत भूषण जैसे देश के जाने माने धुरंधर वकील जिन्होंने याकूब मेमन, कसाब और अफजल का बचाव किया था, आज मुझे इन सबसे बाहर निकालने के लिए तरस रहे हैं।

मुझे दोषी ठहराने में पहले तो निचली अदालत में ही 20 साल लग जाएंगे, फिर मैं उच्च न्यायालय जाऊंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट और हो सकता है इस बीच मैं एमएलए, एमपी या फिर मंत्री भी बन जाऊंगा तो ऐसे केसों से मुझे क्या परेशानी है'?

जज साहब खड़े होकर : मैं आपको सेल्यूट करता हूँ। आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप भटके हुए हो, आपको सुधरने का मौका मिलना चाहिए।

यह लेख कोई मजाक नहीं है।

कन्हैया कुमार, जिग्नेश, उमर खालिद, शीला, राशिद, हार्दिक, अल्पेश, ओवैसी, आजम और अजमल जैसे लोग आज ऐसी ही हरकतों से नेता बने हैं।

धन्य है हमारा 'लोकतंत्र' और 'यहां की जनता।'

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023